• वर्ष-3
• अंक-283
रायपुर, शनिवार
06 जुलाई 2024
• पृष्ठ-8
• मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› स्वस्थ तन और मन के लिए याद रखें..

ब्रिटेन में सत्ता विरोधी लहर

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली

लंदन। आखिरकार इस महान देश के कंधों से एक बोझ हट गया है। परिवर्तन अब शुरू होता है। लंदन में शुक्रवार को सूरज उगते ही यह तीखा बयान कीर स्टार्मर ने विजय रैली में दिया। दरअसल, 4 जुलाई को हुए आम चुनाव में ब्रिटेन की सत्ताधारी

कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी हार हुई है। बड़े विपक्षी दल लेबर ने 2005 के बाद ब्रिटिश चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। लेबर पार्टी को भारी जीत दिलाने के बाद कीर स्टारमर आने वाले घंटों में देश के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे।

निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही सुनक ने अपने इस्तीफे का भी एलान कर दिया है। आइये जानते हैं कि ब्रिटिश चुनाव में ऋषि सुनक को पार्टी क्यों हारी? कंजर्वेटिव सरकार के लिए कौन से मुद्दे भारी पड़ गए?

ब्रिटेन चुनाव के नतीजे कैसे रहे?

4 जुलाई 2024 को ब्रिटेन में 650 संसदीय सीटों के लिए मतदान हुआ। ये चुनाव यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हुए। 5 जुलाई को ब्रिटेन चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं।

इन चुनावों में कुल 392 पंजीकृत पार्टियां रहीं लेकिन मुख्य मुकाबला ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव और मुख्य विपक्षी नेता कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी के बीच हुआ। अब तक 650 में से 648 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। पार्टीवार नतीजे देखें तो विपक्षी लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली हैं। वहीं मौजूदा सत्ताधारी दल कंजर्वेटिव महज 121 सीटें जीती है। वहीं अन्य छोटे दलों की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेट्स ने 71, स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) नौ, सिन फेन सात, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) पांच और रिफॉर्म पार्टी ने चार सीटें जीती हैं। हालांकि, एक सीट पर पुनर्मतगणना के कारण चुनाव का अंतिम परिणाम शनिवार की सुबह तक घोषित नहीं किया जाएगा।

सत्ता विरोधी लहर में बह गए दिग्गज कंजर्वेटिव

ब्रिटेन में पिछले 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। हालांकि, ये वर्ष राजनीतिक दृष्टिकोण से उथल-पुथल से भरे रहे हैं और पिछले आठ वर्षों में पांच कंजर्वेटिव प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन की सत्ता संभाली है। आज आए नतीजों से साफ पता चलता है कि कंजर्वेटिव के खिलाफ तीव्र सत्ता विरोधी लहर थी जिसमें बड़े-बड़े दिग्गज बह गए। इस चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव ने काफी प्रचार किया था लेकिन नतीजों में इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

इन नतीजों ने टोरीज (कंजर्वेटिव पार्टी का चर्चित नाम) को विपक्ष में बैठा दिया है। कंजर्वेटिव के एक से बड़े एक नेता इस चुनाव में परास्त होते गए। उत्तरी इंग्लैंड और मिडलैंड्स क्षेत्र की सीटों पर लेबर और रिफॉर्म पार्टी के हाथों कंजर्वेटिव का सफाया हो गया। उधर दक्षिणी इंग्लैंड के समृद्ध क्षेत्रों में लिबरल डेमोक्रेट्स के हाथों पार्टी का सफाया हो गया, जहां पहले दशकों तक इसका कब्जा था। कई हाई-प्रोफाइल हस्तियां और सत्ता के 14 साल के दौर के चेहरे अपनी सीटें खो बैठे। पेनी मोरडेंट, जैकब रीस-मोग, रॉबर्ट बकलैंड, एलेक्स चाक और अन्य को बड़े नेताओं को अपनी सीटों पर करारी हार मिली। निवर्तमान वित्त मंत्री जेरेमी हंट मुश्किल से ही अपनी सीट बचा सकीं। और सबसे सनसनीखेज हार आखिर तक बची रही। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस अपनी पहले की अति-सुरक्षित सीट हार गईं। इस ब्रिटिश चुनाव से पहले, इस शताब्दी में केवल तीन कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी सीट खोई थी और वे सभी लिबरल डेमोक्रेट के थे, जो कंजरवेटिव के साथ गठबंधन में सरकार का हिस्सा थे।

पांच प्राथमिकताओं पर वादाखिलाफी

जनवरी 2023 में सुनक ने ब्रिटिश लोगों के सामने पांच प्राथमिकताओं के साथ अपना प्रस्ताव रखा था। इसमें मुद्रास्फीति को कम करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, कर्ज कम करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस से मुद्दे को हल करना और अवैध प्रवासियों को रोकना। उस समय उनकी महत्वाकांक्षा की कमी की आलोचना इन पांच वादों के लिए की गई थी। जब तक सुनक ने आम चुनाव की घोषणा की, तब तक केवल मुद्रास्फीति ही लक्ष्य से नीचे थी।

रवांडा फ्लाइट्स पॉलिसी को लेकर उनकी कोशिशें कभी जमीन पर नहीं उतर पाईं। यह रवांडा में शरण चाहने वालों को भेजने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक एक योजना है। इस योजना को अभी भी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अंत में इसने उनकी पार्टी में और असंतोष पैदा किया, चुनावों में टोरीज को नुकसान पहुंचाया।

निगेल फरेज और रिफॉर्म जैसे छोटे दलों इसे चुनावी मुद्दा बनाया में जिसका खामियाजा कंजर्वेटिव सरकार को भुगतना पड़ा।

आपका अहंकार हावी हो जाता है.., मोदी से बातचीत में कोहली ने कहा?

नई दिल्ली। कोहली ने स्वीकार किया है कि उनका अहंकार उन पर हावी हो गया क्योंकि हाल ही में टी20 विश्व कप के दौरान उन्हें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा जहां भारत चैंपियन बना। कोहली अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नहीं थे और वह कम स्कोर पर आउट होते रहे, जबकि साथी सलामी बल्लेबाज और टीम के कप्तान रोहित शर्मा प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ गति निर्धारित करते रहे। कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की, जिन्होंने गुरुवार सुबह अपने आधिकारिक आवास पर भारत की विश्व कप विजेता टीम को आमंत्रित किया था।

मोदी ने बातचीत में कहा कि हम सभी को यहां बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और यह दिन हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में मैं वह योगदान नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता था और एक समय मैंने राहुल भाई से भी कहा था कि मैंने नहीं दिया है अब तक मेरे और टीम दोनों के लिए न्याय। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब स्थिति आएगी तो मुझे यकीन है कि तुम फॉर्म में आ जाओगे। तो हमारे बीच ये बातचीत हुई और जब हम खेलने गए तो मैंने रोहित से कहा, मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं उस तरह से बल्लेबाजी कर पाऊंगा जैसा मैं चाहता था। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल के दौरान मार्को जानसन द्वारा फेंके गए मैच के पहले ही ओवर में तीन चौके लगाने के बाद रोहित के साथ हुई बातचीत का खुलासा किया। कोहली ने कहा कि तो जब हम खेलने गए तो मुझे पहली 4 गेंदों पर 3 चौके लगे, तो मैंने जाकर उनसे कहा कि ये कैसा खेल है, एक दिन लगता है कि एक भी रन नहीं बनेगा और फिर दूसरा दिन आ जाता है। और सब कुछ होने लगता है। इसलिए, जब हमने तीन विकेट खो दिए, तो मुझे खुद को स्थिति के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। मेरा ध्यान केवल इस बात पर था कि टीम के लिए क्या महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मुझे उस क्षेत्र में धकेल दिया गया है और मैं इसके पीछे का कारण नहीं बता सकता।

रूस से सेना को मिले एके-203 राइफल्स

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8-9 जुलाई को रूस यात्रा प्रस्तावित हैं। जहां वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मास्को दौरे से पहले ही भारतीय सेना को 35,000 एके-203 (एके-203) कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी कर दी गई है। इससे पहले इसी साल मई में 27 हजार एके-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई थीं। खास बात यह है कि इन राइफलों को बनाने में इस्तेमाल हुए 25 फीसदी पार्ट भारत में तैयार किए गए हैं। इन राइफलों को भारत-रूस ज्वॉइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से इन असाल्ट राइफलों को बनाने के लिए जुलाई 2021 में रूस के साथ 5000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इस सौदे के तहत देश में 6.7 लाख से ज्यादा,च-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाना है। जिन्हें एक ज्वॉइंट वेंचर के तहत इंडो-रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ये राइफल्स बनाएगी। इंडो-रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2019 में भारत के तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (अब एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड) और रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और कलाश्निकोव के बीच हुई थी।

कलाश्निकोव एके-203 दरअसल एके-200 असॉल्ट राइफल का एक वैरिएंट है, जिसे भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले 7.62म39 मिमी कारतूस के लिए बनाया गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाई गई ये राइफल्स भारतीय सेना को और मजबूती देंगी। भारत-असेंबल कलाश्निकोव एके-203 असॉल्ट राइफलें यूपी के अमेठी जिले बनाई गई हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, पहली 70,000 राइफलों का उत्पादन भारत में किया जाएगा, जिसमें भारतीय पार्ट्स की सीमा को चरणबद्ध तरीके से 5 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी किया जाएगा। शेष 6 लाख राइफलों का उत्पादन 100 फीसदी स्वदेशीकरण के साथ किया जाएगा। उम्मीद है कि 2-3 साल के भीतर एके-203 राइफलों का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा।

आकांक्षीय विकासखंण्ड गौरेला में संपूर्णता अभियान का किया शुभांरभ

संपूर्णता अभियान के तहत 6 इंडिकेटर पर शत प्रतिशत लाएं उपलब्धि: साहू

रायपुर। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्री तोखन साहू ने केन्द्र तथा राज्य शासन की प्राथमिकता वाली आकांक्षी विकासखण्ड के तहत आज गौरेला विकाखण्ड के ग्राम पंचायत सारबहरा में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा निर्देशित 6 इंडिकेटरों पर शत प्रतिशत उपलब्धि लाने कहा। श्री साहू ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संपूर्णता अभियान के सभी इंडिकेटरों को संतृप्त करने के लिए योगदान देकर स्वास्थ्य, समर्थ और समृद्ध ब्लाक-जिला बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिज्ञा दिलाई। केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी ब्लाक के सभी हितग्राहियों को योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए 6 इंडिकेटर पर फोकस किया है। उन्होने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा निर्देशित 6 इंडिकेटरों पर शत प्रतिशत उपलब्धि लाने कहा। इनमें प्रथम तिमाही के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल, लक्षित आबादी में मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की जांच, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं की नियमित रूप जांच और उनको पूरक पोषण वितरण, मृदा परीक्षण और स्व-सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड प्रदान करना शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जीवन में आये सुखद बदलाव पर आधारित संदेश का प्रसारण भी किया गया।

प्रमुख समाचार

राहुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, लोको पायलटों से की मुलाकात

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के लगभग 50 लोको पायलटों से मुलाकात की। पार्टी के मुताबिक, उनसे बातचीत के दौरान लोको पायलटों ने मुख्य रूप से 46 घंटे के साप्ताहिक आराम की मांग करते हुए अपर्याप्त आराम की शिकायत की। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पर्याप्त ब्रेक के बिना लंबे समय तक काम करने से अत्यधिक तनाव होता है और एकाग्रता में कमी आती है जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। बयान में कहा गया है कि विशाखापत्तनम में दुर्घटना की हालिया जांच सहित कई रिपोर्टों में रेलवे द्वारा यह स्वीकार किया गया है। पार्टी ने कहा कि लोको पायलटों की मांग है कि उन्हें साप्ताहिक 46 घंटे का आराम मिले। इसका मतलब यह है कि शुक्रवार दोपहर को घर लौटने वाला ट्रेन चालक रविवार की सुबह से पहले ड्यूटी पर लौट आएगा। रेलवे अधिनियम 1989 और अन्य नियमों में पहले से ही प्रति सप्ताह 30 + 16 घंटे आराम का प्रावधान है, जिसे लागू नहीं किया जा रहा है।

दो सप्ताह में 12 पुल ढहे, 11 इंजीनियर निलंबित

पटना। बिहार में दो सप्ताह में कुल 12 पुल ढहने के बाद, राज्य सरकार ने शुक्रवार को 11 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने नए पुलों के पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया है। निर्माण की लागत दोषी पाए गए ठेकेदारों पर लगाई जाएगी। यह निर्णय उड़न दस्तों द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद लिया गया, जिसमें बताया गया था कि पुलों के ढहने के पीछे मुख्य कारण इंजीनियरों की लापरवाही और निगरानी की अप्रभावीता थी। राज्य जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इंजीनियरों पर उचित देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया और घटनाओं के पीछे ठेकेदारों की मेहनत पर प्रकाश डाला। मीडिया को जानकारी देते हुए प्रसाद ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इंजीनियरों ने उचित देखभाल नहीं की और ठेकेदार भी मेहनती नहीं थे। इससे पहले, गुरुवार को बिहार के सारण जिले में एक और पुल के ढहने के साथ, पिछले 17 दिनों में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर बारह हो गई।

समलैंगिक विवाह के फैसले को चुनौती, याचिका पर 10 को सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को अपने पिछले साल के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने वाला है, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 10 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ पिछले साल 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर चैंबर में विचार करेगी। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए एक मजबूत वकालत की थी ताकि उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े जो दूसरों के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए सभी जिलों में सुरक्षित घर बनाए गए हैं जिन्हें गरिमा गृह के रूप में जाना जाता है। उत्पीड़न और हिंसा का सामना करने वाले समुदाय के सदस्यों और समर्पित हॉटलाइन नंबरों का उपयोग करें जिनका उपयोग वे परेशानी की स्थिति में कर सकें।

हाथरस हादसे पर एसआईटी ने योगी को सौंपी जांच रिपोर्ट

लखनऊ। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित एसआईटी ने उस त्रासदी पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में कम से कम 123 लोगों की जान चली गई थी। यह भगदड़ मंगलवार को धार्मिक उपदेशक नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, के सत्संग के दौरान हुई। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। यह एसआईटी रिपोर्ट एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी के तहत तैयार की गई थी। 15 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी के सदस्यों ने भगदड़ का कारण जानने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, कार्यक्रम से जुड़े लोगों और सेवादारों से बात की।

हिंडनबर्ग केस में चीन का हाथ?

नई दिल्ली। भारत के सबसे वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया है कि चीनी लिंक वाले एक अमेरिकी-आधारित व्यवसायी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसके कारण जनवरी-फरवरी 2023 में अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में चीन एंगल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी के शेयरों की कम बिक्री के संबंध मे हमने केवल हिंडनबर्ग के बारे में सुना है, उन्होंने एक फंड के कहने पर अदानी समूह पर शोध रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे मार्क किंग्डन और अनला चेंग नाम के एक जोड़े ने प्रमोट किया था। शोध के बाद हमने पाया कि कोटक को व्यापार करने के लिए नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने एक ऑफशोर खाता स्थापित किया और इस जोड़े के लगभग 40 मिलियन के मास्टर फंड से पैसा लिया। इस राशि का उपयोग कोटक के माध्यम से मॉरीशस मार्ग के माध्यम से बड़े पद लेने के लिए किया गया था। अडानी इस विचार से सहमत हैं कि एक बार नकारात्मक रिपोर्ट सामने आने के बाद वे बेच देंगे और बाहर चले जाएंगे।

स्वागतेय

मुस्लिमों ने कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो!

गिरीश पंकज

छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज ने पिछले दिनों जो पहल की है, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत देश के अधिकतर मुसलमान गाय का सम्मान करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले दिनों रायपुर में आयोजित महासभा में मुस्लिम समाज के जागरुक लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग क्यों करते ? उन्होंने यह महत्त्वपूर्ण मांग करते हुए देश के सामने एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। दिल्ली में बैठी सरकार को अब इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार को भी केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखना चाहिए कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मुस्लिम बंधुओं ने एक और महत्वपूर्ण मांग की, जिसके बारे में इन पंक्तियों का लेखक समय-समय पर बेचैन होकर लिखता रहा है। वो है- गौ मांस के निर्यात पर तुरंत रोक। भारत जैसा गौ प्रेमी राष्ट्र गौ मांस के निर्यात में अगर अव्वल होता जा रहा है, तो यह गर्व की नहीं शर्म की बात है । इसलिए मुस्लिम बंधुओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि गौ मांस का निर्यात बंद किया जाए और जितनी भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए । उनकी यह मांग भी बहुत अच्छी है कि पशु परिवहन और तस्करी पर रोक लगनी चाहिए ताकि गौ रक्षा के नाम पर होने वाली मोब लिंचिंग पर भी रोक लग सके। इसमें दो राय नहीं कि गौ सेवा के नाम पर कुछ लोग चंदाखोरी का ही काम करते हैं। इस देश का आम आदमी गाय के प्रति अतिरिक्त श्रद्धा रखता है इसलिए गौशाला का चंदा मांगने अगर लोग घर तक आते हैं, तो उदार होकर को सहयोग कर देता है । लेकिन देखा यही गया है कि गौशाला चलने वाले लोग गायों की सेवा नहीं करते, वरन सेवा की आड़ में मेवा खाने का काम करते हैं। गाय तो मूक पशु है। वह कुछ बोल नहीं सकती। अगर वह भूखी है तो भी नहीं बोल सकती ।प्यासी है तो भी नहीं बोल सकती। इसी का लाभ उठाकर अनेक गौशालाओं में गायों की दुर्दशा देखने को मिलती है। रखरखाव के अभाव में बेचारी हमारी गौ माता अकाल मौत मरती हैं। छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज की यह मांग भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आरंग नामक कसबे में पिछले दिनों गाय को बचाने के नाम पर जो हत्या हुई थी, उसे आत्महत्या का रूप न दिया जाए वरन वह हत्या ही थी। हिंदू समाज के सक्रिय गौ सेवकों से मैं आग्रह करूँगा कि आप गौ तस्करी रोकने के लिए खतरे उठाकर जो काम करते हैं, वह निसंदेह अभिनंदनीय है, वंदनीय है । लेकिन आप हिंसा का सहारा न लें। तस्करों को आप पकड़े और पुलिस के हवाले करें। फिर पुलिस उनपर कार्रवाई करके जेल भेजेगी। आप कानून अपने हाथ में न लें । लेकिन जब कानून हाथ में लेकर गौ तस्करों की निर्मम पिटाई होती है और उनकी मौत हो जाती है, ऐसा करने के कारण ही अनेक लोग हिंदू समाज के कुछ लोगों को हिंसक कहने लगे हैं और किसी की हत्या करना अपने आप में हिंसा है हमें गाय के प्रति प्रेम है अद्भुत प्रेम है लेकिन इस प्रेम का मतलब यह तो नहीं सामने वाले की हम हत्या कर दें इतनी उत्तेजना अच्छी नहीं और तस्करों को हम पकड़े बेशक उन पर दो चार हाथ हम चलाएं भी लेकिन

ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसकी जान चली जाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदूबहुल भारत वर्ष में हिंदू समाज एकजुट होकर सरकार पर दबाव नहीं बनाता कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जिन मुसलमानों पर आए दिन तथाकथित गौ भक्त तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, वे लोग गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं! यह कैसी विसंगति है ? इस पर हमें विचार करना चाहिए । मैंने अपने उपन्यास एक गाय की आत्मकथा में एक मुस्लिम व्यक्ति को पात्र बनाया है, जो गौ सेवा के काम में लगा रहता है । एक गौशाला में चार बीमार गायों को गौशाला का सेठ कसाई को बेचना चाहता है। और स्वाभाविक है कि बीमार गायों को कोई कसाई ही खरीदेगा। जब मुस्लिम पात्र मुजफ्फर अली को पता चलता है कि सेठ बीमार गायों को बेच रहा है तो वह उनके पास जाता है और उनके मुँह पर चेक मारता है और कहता है वह गाय मैं खरीद लूंगा ।सेठ भीतर से पानी-पानी तो हो जाता है। अब क्या बोले। हिंदू गाय बेच रहा है, मुसलमान गाय खरीद रहा है!! एक दृश्य में मैंने यह दिखाया है कि एक हिंदू बाजार में मांस खरीद रहा है और वहीं एक मुस्लिम सब्जी-भाजी खरीद रहा है। यह जो स्थितियां मैंने बताई हैं, वे काल्पनिक नहीं, यह मेरी अपनी देखी हुई हैं। धीरे-धीरे हमारा तथाकथित हिंदू समाज उदार होकर गौ माता से दूर हो चुका है उसे उसे अब कुत्ते प्यारे लगने लगे हैं। कितनी बड़ी विसंगति है कि जो कुत्ते पाल रहा है, कुत्ते से अपने आप को मस्ती के साथ चटवा रहा है, वह तो %एनिमल लवर% हो गया मगर जो गोपालन कर रहा है, वह हो गया पिछड़ा हुआ आदमी !! समाज की बदलती हुई घटिया सोच के कारण धीरे-धीरे गायों की संख्या कम होती जा रही है । खेतों में ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है इसलिए बैल बेकार हो रहे हैं। और जब बैल बेकार हो गए तो स्वाभाविक है वे भूखे मरेंगे या काटने के काम आएंगे। और हमारे यहां पशुओं का वध करने में बहुतों को कोई संकोच नहीं होता ।इस मामले में सभी धर्मनिरपेक्ष हैं। (खैर ! यह अलग बहस का विषय है।) फिलहाल तो मुझे छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज पर गर्व हो रहा है कि जो काम हिंदू समाज को करना था, अपने आप को जो सनातनी कहते हैं, उन सबको करना था , वह काम मुस्लिम समाज ने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में एक बड़ा सम्मेलन देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू समाज करेगा, जिस में गौ माता पर गंभीर-विमर्श किया जाएगा और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग प्रस्ताव पारित होगा। गौ मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए, यह मांग भी की जाएगी। एक मांग यह भी होगी कि देश में चल रहे सारे कसाई खाने बंद होने चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग या गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग पहले नहीं उठी है ।

जांजगीर में पांच तो कोरबा जिले में चार

अब तक कुएं में उतरने से नौ लोगों की मौत

कोरबा/जांजगीर। छत्तीसगढ़ में कुआं काल बना हुआ है। आज शुक्रवार को प्रदेश के अलग-अलग दो जिलों में कुएं में उतरने से नौ लोगों की मौत हो गई है। जांजगीर-चांपा में पिता और दो बेटे समेत पांच, तो कोरबा जिले में पिता-पुत्री समेत चार लोगों की मौत हुई है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। दरअसल, बरसात के दिन आने पर कुएं की साफ-सफाई करने के लिए उतरे हुए थे। कुएं में गैस रिसाव के चलते उनकी मौत हो गई, इन्हें बचाने के लिए एक-एक कर उतरे नौ लोगों की मौत हो गई है। कुएं में जहरीली गैस की वजह से सभी का दम घुटने लगा, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई।

जांजगीर-चांपा जिले के बिर्रा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम किकिरदा में उस वक्त मातम छह गया, जब गांव के ही कुएं में पांच लोगों की मौत हो गई। दरअसल, कुएं में गिरी लकड़ी को निकालने के लिए एक व्यक्ति कुएं में उतर गया। कुएं से निकल रही जहरीली गैस से उसकी मौत हो गई। उसे बचाने के लिए पड़ोस में रह रहे चार लोग एक-एक कर उतरे। वहां जहरीली गैस की वजह से उनकी भी मौत हो गई। मृतकों का नाम रामचंद्र जायसवाल 60 वर्ष, पड़ोसी रमेश पटेल 50 वर्ष, रमेश पटेल के दो बेटे जितेंद्र पटेल 25 वर्ष, राजेंद्र पटेल 20 वर्ष, एक और पड़ोसी टिकेश्वर चंद्रा 25 वर्ष बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टिकेश चंद्रा की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी। रमेश पटेल खेती किसानी का काम करता था, उसके पुत्र जितेंद्र पटेल की दो साल पहले शादी हुआ था, उसका 5 माह का बच्चा है। वहीं राजेंद्र पटेल ने अपनी 10वहीं तक की पढ़ाई की है, जिसके बाद अपने पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाया करता था।

दूसरी ओर कोरबा जिले के कटघोरा थानांतर्गत ग्राम जुराली के डिपरा पारा में चार लोगों की कुआं में डूबने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कुंआ में ग्रामीण के गिरने के बाद उसे बचाने के लिए बेटी कुंआ में कूद गयी। इसके बाद परिवार के ही दो अन्य लोग कुआं में नीचे उतरे, लेकिन सभी की मौत हो गई। जुराली निवासी शिवचरण पटेल कुएं की सफाई कर रहा था इस दौरान वह नीचे गिर गया। उसे देखकर उसकी बेटी सपीना नीचे उतरी, जहां उसकी भी मौत हो गई। दोनों को कुएं में गिरा हुआ देख मनबोध पटेल, जरूर पटेल नीचे उतरे। थोड़ी देर बाद उनकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुएं में गैस रिसाव के चलते चारों की मौत हुई है।

मुख्यमंत्री ने जताई गहरी संवेदना, प्रत्येक मृतक के परिजन को 9-9 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश

प्रदेश में कोरबा जिले में कुएं से डूबने से 4 लोगों की और सक्ती जिले में कुएं में जहरीली गैस से हुई दुर्घटना से 5 लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया है तथा पीड़ित परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को 9-9 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं। इसमें से 4-4 लाख रुपए आरबीसी छह-चार के अंतर्गत तथा मुख्यमंत्री की ओर से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि शामिल है। उल्लेखनीय है कि सक्ती जिले में कुएं में हुए रिसाव में पिता और दो पुत्रों सहित पांच लोगों की मौत हुई जबकि कोरबा में पिता और बेटी समेत चार लोगों की मृत्यु हुई।

अवैध काम करने वालों के खिलाफ होगी जांच: टंकराम

धमतरी। जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार को जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक ली। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में मंत्री ने सभी विभागों के कामों की समीक्षा की। साथ ही सरकार की योजनाओं का जमीनी हाल चाल जाना। धमतरी जिले में पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बावजूद रेत के अवैध कारोबार पर मंत्री पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही।

मंत्री बनने के बाद टंकराम वर्मा ने पहली बार अपने प्रभार क्षेत्र धमतरी में विभागीय समीक्षा बैठक ली है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासन के आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 6 से 20 जुलाई तक आयोजित होने वाले राजस्व पखवाड़ा की समीक्षा की। राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री ने कहा- आम आदमी राजस्व से जुड़ा होता है। नामांकन, सीमांकन के काम होते हैं। छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। कार्य में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। बेवजह प्रकरणों को रोकने वाले अधिकारियों को नोटिस भिजवाए गए हैं।

टंकराम वर्मा ने कहा सभी विभागों का कामकाज सही से चल रहे हैं। जनता की सेवा के लिए हम यहां हैं। नकली खाद, बीज, दवाई इत्यादि के बिक्री पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान सम्मान निधि की राशि पात्र किसान को मिले, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिले में अवैध उत्खनन, अवैध शराब, सटोरिया इत्यादि पर भी कार्रवाई की जा रही है।

समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन के लिए जिले में की गई व्यवस्था की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री श्री वर्मा ने बारिश में होने वाली जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। साथ ही मंत्री टंकराम वर्मा ने साफ किया कि सभी विभागों का काम ठीक से चल रहा है।अवैध कामों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सांसद ज्योत्सना ने कहा सीएसईबी भी बीएसपी की तर्ज पर दें बसाहट

बारिश में लोगों को घर से बेदखल करना ठीक नहीं

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कोरबा स्थित सालों पुराने आवासीय कॉलोनी में रह रहे लोगों को घर छोड़ने के नोटिस को कोरबा सांसद ने अनुचित करार दिया है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि बारिश के समय इस तरह लोगों को बेदखल करना ठीक नहीं है।

बता दें कि सीएसईबी कोरबा पूर्व के प्रबंधन ने एसएफ टाइप कॉलोनी के लोगों को दो दिन पहले नोटिस जारी कर मकान खाली करने कहा है घरों में पानी-बिजली आपूर्ति बंद करने की भी बात कही गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए सांसद ने सीएसईबी और कोरबा जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। इस पत्र में सासंद ने लिखा- सीएसईबी का कोरबा में स्थापित पहले विद्युत संयंत्र ने देश-प्रदेश को रौशन किया। इसकी वजह से कोरबा को एक पहचान मिली। इसकी कॉलोनी में रह रहे लोगों को ऐन बरसात के समय बेदखल करने का प्रयास निवासरत परिवारों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। प्रदेश में सरकार बदलते ही रुख दिखाना शुरू हो गया है। कॉलोनी के आवासों में सालों से रह रहे लोगों के पास दूसरा कोई आशियाना नहीं है और ऐसे में जरूरत है कि कोई ठोस और स्थायी उपाय किये जाएं।

सांसद ने पत्र में आगे लिखा- सरकार इन्हें बेदखल कराने की बजाय भिलाई स्टील प्लांट की तर्ज पर सीएसईबी की कालोनियों में स्थायी बसाहट देने की दिशा में काम क्यों नहीं करती? मौजूदा आवासों की मरम्मत कर उसमें रह रहे लोगों से सुविधा के नाम पर शुल्क और एक निर्धारित किराया लेकर भी आवास की बड़ी समस्या से राहत देने के साथ-साथ आवश्यक सुधार व संधारण के लिए शुल्क भी लिया जा सकता है।

सांसद ने कहा कि सरकार की आवासीय योजनाओं का लाभ आज भी हजारों जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है। ऐसे सैकड़ों परिवार सीएसईबी के आवासों में रहकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, जिन्हें बेदखल करने की बजाय स्थायी समाधान देने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि फिलहाल बरसात के मौसम तक किसी भी तरह की बेदखली और बिजली, पानी की सुविधा बाधित करने जैसी कोई भी कार्रवाई न करें। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन से भी आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जाहिर की है।

मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने उतारा ग्रामीण को मौत के घाट

नारायणपुर। इन दिनों छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षाबलों के जवाब लाल आतंक को मात दे रहे हैं। इस बीच बौखलाहट में शुक्रवार को नारायणपुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों को शक था कि ग्रामीण पुलिस का मुखबिर है। वहीं, इस हत्या के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

दरअसल, नारायणपुर जिले अबूझमाड़ के ग्राम पंचायत थुलथूली की ये घटना है। यहां नक्सलियों ने गायता गांव के चैतूराम मंडावी की हत्या कर दी। सात जून को हुए एनकाउंटर में जवानों ने पांच नक्सलियों को मार गिराया था। इससे बौखलाए नक्सलियों ने चैतूराम मंडावी पर मुखबिरी का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी मुताबिक नक्सली ग्रामीण को पास के जंगल में ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दिए। हत्या के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

दरअसल, नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सल ऑपरेशन 30 जून को लॉन्च किया गया। यहां के कोहकामेटा, इरकभट्टी, मोहंती और सोनपुर के जंगलों में डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की टीम को भेजा गया था। दो जुलाई को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ हुआ था। 2 जुलाई को अबूझमाड़ के घमंडी और हितुलवाड़ के जंगल में सुबह से ही माओवादियों और जवानों के बीच कई बार रुक-रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग के दौरान 5 नक्सलियों का शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसी घटना से नाराज नक्सलियों ने ग्रामीण चैतूराम मंडावी को मौत के घाट उतार दिया।

डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पर अभद्रता का आरोप

धरने पर बैठे पार्षद अनूप यादव सीआईएसएफ के जवान तैनात

कोरबा। कोरबा के दीपका नगर पालिका परिषद दीपका के पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव ने डीएवी पब्लिक स्कूल गेवरा के प्रिंसिपल मनीषा अग्रवाल पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है।

अनूप यादव शुक्रवार को सुबह स्कूल के सामने धरने में बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की माने तो स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना आम बात है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव के द्वारा एडमिशन संबंधी जानकारी के लिए स्कूल के प्राचार्य से मिलने गया था जहां डीएवी के प्रिंसिपल ने किसी भी संबंध में जानकारी देने से मना करते हुए अपने दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

दरअसल गेवरा दीपका क्षेत्र में डीएवी पब्लिक स्कूल आम जनता एवं एसईसीएल कर्मचारियों की पहली पसंद है और विद्यालय में जितनी सीट है उससे कई गुणा लोग वेटिंग में रहते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता। यहां एडमिशन के लिए, पार्षद, यूनियन नेता, विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक के पत्र आने की बात आम है। साथ ही इस विद्यालय का संचालन एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के निगरानी में किया जाता है। बहरहाल प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिऐ सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मजदूरों से भरा ऑटो पलटने से चार लोग गंभीर रूप से घायल

जगदलपुर। जगदलपुर में अशोका लीलैंड के सामने शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गई। इस हादसे में ऑटो में सवार सात मजदूरों में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया, जहाँ उन्हें उपचार के लिए मेकाज में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की सुबह डिमरापाल में रहने वाले शांति, पुष्पलता, सुदरी, सुदनी के अलावा अन्य मजदूरों को लेकर जगदलपुर घर काम मे मजदूरी करने के लिए लेकर जा रहा था कि अचानक अशोका लीलैंड के सामने अचानक से ड्राइवर ने ऑटो से अपना नियंत्रण खो दिया और पलट गई। इस हादसे में पांच लोग घायल हुए, जबकि अन्य को सामान्य तौर पर चोट आई। घायलों को बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया जहाँ उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया है।

स्कूल के हेड मास्टर ने 5 वीं कक्षा की छात्रा से की मारपीट

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 5वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सरकारी स्कूल में बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल के हेड मास्टर पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में युवा कांग्रेस ने मारपीट करने वाले हेडमास्टर पर कार्रवाई ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, मुंगेली विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला चमारी के प्रधान पाठक टुकराम खांडे ने 29 जून को 5वीं कक्षा की छात्रा गौरी साहू को डंडे से मारपीट कर लहू लुहान कर दिया। टीचर ने पहले छात्रा को डराया, फिर डंडे से मारकर दाहिने आंख के पास चोट पहुंचाई। इस घटना में छात्रा के आंखों के नीचे गंभीर चोट आई है। जिसके छात्रा के परिजनों ने 1 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित आवेदन कर प्रधान पाठक पर उचित कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद भी आरोपी शिक्षक खांडे के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई।

ऑनलाइन महादेव सट्टा एप पैनल संचालक की हुई मौत

दुर्ग। ऑनलाइन महादेव सट्टा एप हैदराबाद पैनल संचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसने पुलिस की कार्रवाई के दौरान तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक का नाम सुजीत कुमार साव निवासी भिलाई बताया जा रहा है। पिछले सप्ताह एंटी साइबर क्राइम यूनिट की टीम ने हैदराबाद में दबिश देकर ऑनलाइन महादेव सट्टा एप का पैनल चलाने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए सभी आरोपी भिलाई के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटाप, मोबाइल समेत लाखों का लेखा-जेखा बरामद किया। एंटी साइबर क्राइम यूनिट एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि भिलाई के कुछ युवक ऑनलाइन महादेव सट्टा एप का पैनल हैदराबाद के तेलंगाना में चला रहे थे। सूचना मिलने के बाद एक टीम गठित कर टीम को रवाना किया गया। जहां एक मकान में छापामार कार्रवाई की। जहां पैनल संचालित करते एक नाबालिग समेत छह को गिरफ्तार किया था।

ग्रामीणों ने पुल निर्माण को लेकर किया चक्काजाम

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर मुख्यालय से मैनपुर कला पंडरीपनी जाने वाले मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को फिर सुबह ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। 90 के दशक में परियोजना मद से बनाया गया छोटा पुल 7 साल पहले टूट गया था। इसके बाद से ग्रामीण हर साल यहां पुल निर्माण के लिए सड़क जाम कर पुल निर्माण की मांग उठाते आ रहे हैं। बता दें, ग्रामीणों ने पहले से ही आज होने वाले आंदोलन को लेकर चेतावनी दी थी। आज सुबह 9 बजे से जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे को जाम कर दिया था। जाम के कारण हाइवे में दोनों तरफ घंटों गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम, एसडीओपी के अलवा पीडब्ल्यूडी सेतु विभाग के एसडीओ एस के पंडोले मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर रास्ता खुलवाया। एसडीओ ने बताया कि इस स्थान पर 100 मीटर लंबे हाई लेबल पुल के लिए 2024 में रुपए की मंजूरी मिल गई है। कागजी कार्रवाई जारी है।

व्यापारी के गोदाम में छापेमारी पीडीएस का चना-गुड़ जब्त

बीजापुर। जिले में पीडीएस खाद पदार्थ की कालाबाजारी पर बीजापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गल्ला व्यापारी के घर दबिश दी। व्यापारी के घर से भारी मात्रा में पीडीएस का गुड़ और चना बरामद किया गया। पुलिस ने 111 बोरी पीडीएस का चना और 50 क्विंटल गुड़ जब्त किया। कलेक्टर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीजापुर के जैतालूर के कालेजपारा के गल्ला व्यापारी सुजित जायसवाल के घर शुक्रवार को पुलिस ने दबिश दी। व्यापारी के घर से पीडीएस का चना और गुड़ के अवैध भंडारण की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और तकरीबन 111 बोरी चना और 50 क्विंटल गुड़ जब्त किया। जब्त गुड़ और चने की कीमत लगभग 4 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के एक्शन और अवैध भंडारण की सूचना पर कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा इस तरह की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

निगरानी बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हिस्ट्रीशीटर के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

दुर्ग। दुर्ग में जिला पुलिस ने निगरानी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की है। बीएसपी की टीम ने हिस्ट्रीशीटर पिंकी राय के ढाबे और दुकान पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। बीएसपी के प्रवर्तन विभाग की टीम के साथ मिलकर पुलिस लगातार निगरानी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नेवई थाना के हिस्ट्रीशीटर पिंकी राय का ढाबा और दुकान पीआर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया।

पिंकी राय दुर्ग जिले का एक हिस्ट्रीशीटर है जो बीएसपी के अवैध कब्जे पर कई सालों से कब्जा कर ढाबा संचालित कर रहा था। पिंकी राय को नोटिस देने के बाद पुलिस और बीएसपी की टीम ने उसके ढाबा और दुकान पर कार्रवाई की है। पिंकी राय के खिलाफ नेवई थाने में 14 से अधिक मामले दर्ज हैं। 23 मई 2024 को पिंकी राय और उसकी गैंग ने रिसाली नगर निगम के कर्मचारी विपिन का अपहरण किया था और अपने दुकान में लेकर जाकर विपिन के साथ मारपीट की थी। पिंकी राय, शैलेष निर्मलकर एवं ओम चौधरी ने कार में बिठाकर अपहरण किया जिसके बाद विपिन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पिंकी राय के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हुई थी।

लखपति दीदी बनने के सपने को कर रही साकार-गीदम की महिलाएं

दंतेवाड़ा। श्रीमती मंगलदई महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रही है और कामयाबी का परचम लहरा रही है। मेहनत करने वालों की राह स्वयं ही खुल जाती है। इस बात को दूरस्थ अंचल जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के गीदम विकासखंड अंतर्गत 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित हिड़पाल ग्राम पंचायत में माँ गौरी स्व-सहायता समूह की महिलाएं चरितार्थ कर रहीं हैं। सुदूर वनक्षेत्र में निवासरत ये ग्रामीण महिलाएं आज सीमेंट ईट बनाने जैसा श्रम साध्य कार्य को अंजाम देने में जुटी हैं। ईंट बनाने के काम में 5 पुरूष मिस्त्रियों ने महिलाओं को इस काम में सहयोग करते हुए तैयारी के संबंध में समझाया फिर उन्हें ईट बनाने की मशीन संचालन करना, रेत, डस्ट में सीमेंट की मात्रा की मिलावट के बारे में जानकारी दी। इस तरह 10 महिलाओं ने शुरूआती दौर में 500 ईंट निर्माण की तैयारी की।

ईंट निर्माण की प्राथमिक जानकारी मिलने से महिलाओं को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आने वाले समय पर वे स्वयं मशीन ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मॉ गौरी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इसे अब अपनी आजीविका का साधन बनाने का मन बना लिया हैं। ज्ञात है कि राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास निर्माण को प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट की मांग बढ़ गई है। ईंट निर्माण से जुड़ी मॉ गौरी स्व-सहायता समूह की श्रीमती कमला कोर्राम का इस संबंध मे कहना है कि ईंट निर्माण कार्य से जुड़ कर उन्हें बहुत अच्छी लग रही है और काफी खुशी भी हो रही है क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है।

अन्य सदस्य श्रीमती तुलसी कश्यप ने बताया कि शुरूआत में निश्शुल्क डस्ट एवं सीमेंट जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया। ईंट बनाने के सांचे भी उन्हे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्राप्त हुए हैं। साथ ही ईंट बनाने के लिए प्रशासन की ओर से उन्हें निश्शुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन के प्रति अभार व्यक्त किया।

आने वाले समय पर रेती, डस्ट एवं सीमेंट की खरीदी का पूरा दारोमदार समूह पर रहेगा। समूह की अन्य महिला श्रीमती मंगलदई ने आगे और जानकारी देते हुए कहा कि मॉ गौरी स्व सहायता समूह के द्वारा बैंक से 3 लाख रूपये का ऋण भी लिया गया है। पहले हम सभी महिलाएं लाल ईंट निर्माण कार्य से जुड़ी हुई थी जिसमें मिट्टी को अच्छे से मिलाकर ईंट बनाया जाता था। अभी इसमें फर्क इतना ही है कि मशीन के रेती, डस्ट, सीमेंट तीनों पदार्थों को एक साथ मिक्सर मशीन में डाल कर घुमाया जाता है और जिससे मिक्स होने के बाद उसे ईंट बनाने वाले मशीन में डाला जाता है। जिससे एक बार में 10 ईंट बन कर निकलती है। ईंट निर्माण के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वरोजगार की एक और राह खुल गई है। इस प्रकार अब जिले की हर एक ग्रामीण महिला शासन की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना के तहत लखपति दीदी बनने का सपना साकार कर सकती है।

संक्षिप्त समाचार

डिप्टी सीएम साव और शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात

रायपुर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव

और विजय शर्मा ने दिल्ली प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। वहीं उपमुख्यमंत्री साव और शर्मा ने रेल मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और राजकीय गमछा पहनाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने एक्स पोस्ट पर शेयर की है। अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट शेयर कर लिखा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा से मुलाकात की और प्रदेश में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

डिजिटल सचिवालय के लिए राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण

रायपुर। डिजिटल सचिवालय परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आज राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों को चिप्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। चिप्स द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के मार्गदर्शन में एचआरएमएस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसमें अवकाश के लिए आवेदन, अचल संपत्ति विवरण और गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरा जा सकेगा। राजभवन में भी डिजिटल एचआरएमएस सॉफ्टवेयर के संचालन हेतु आवश्यक तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित चिप्स के प्रशिक्षणकर्ताओं ने सभी शंकाओं का उचित समाधान किया। प्रशिक्षण में उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, अवर सचिव सुश्री अर्चना पाण्डेय, नियंत्रक श्री संजय विश्वकर्मा सहित राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बृजमोहन के बाद रमन सिंह को भी खो कर दिया है : भूपेश बघेल

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल के बाद अब डॉ. रमन सिंह को भी खो कर दिया है। बड़े नेता कुर्सी बचाने केंद्रीय नेतृत्व के पास दौड़ लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि साय सरकार में उथल-पुथल की स्थिति है। सरकार से 4 मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चा है। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धरम लाल कौशिक, राजेश मूणत जैसे कई बड़े नेता मंत्री बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। यही नहीं विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी खाली पड़ा है।

कांग्रेस नेता कुणाल शुक्ला के घर पहुंची राजस्थान पुलिस

रायपुर। कांग्रेस नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला के घर शुक्रवार सुबह राजस्थान पुलिस पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ टिपण्णी करने पर राजस्थान में एफआईआर दर्ज किया गया था। राजस्थान पुलिस ने नोटिस देते हुए कुणाल शुक्ला से 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बगिया पहुंचने पर आत्मीय स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बगिया

हेलीपेड पहुंचे, हेलीपेड पर जंप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री परदेशी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी और आरंग विधायक भी बगिया पहुंचे। बगिया स्थित शासकीय हाईस्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।

राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव, नवमी में प्रवेशित 30 छात्राओं को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वितरित की साइकिल

जब मुख्यमंत्री से मिली साइकिल तो छात्राओं ने सामूहिक रूप से घंटी बजाकर जताया उत्साह

रायपुर। जशपुर जिले के ग्राम बगिया में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर आज यहां छात्र छात्राओं के लिए खुशियों भरा दिन रहा। जहां एक ओर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया और जशपुर के माटी पुत्र मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। वही दूसरी तरफ शाला प्रवेशोत्सव में नव प्रवेशी बच्चों के अभिनंदन के साथ उन्हें उपहार देने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने 9 वीं कक्षा में प्रवेशित छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया। छात्राओं ने साइकिल मिलने की खुशी सामूहिक रूप से साइकिल की घंटी बजाकर जाहिर की और मुख्यमंत्री श्री साय का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी छात्राओं को अच्छे से पढ़ाई कर बेहतर परिणाम के साथ अपने माता-पिता और बगिया सहित प्रदेश का नाम रोशन करने की बात कहते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री राधेश्याम राठिया, विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत, विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहेब, जिला पंचायत अध्यक्ष जशपुर श्रीमती शांति भगत, उपाध्यक्ष श्री उपेन्द्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 9 वीं की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण--

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना से छात्राओं को मुफ्त साइकिल प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत शासकीय स्कूलों में पढने वाली कक्षा 9 वीं की छात्राओं को निशुल्क साइकिल प्रदान की जा रही है, ताकि संसाधनों के अभाव में और दूरी के कारण छात्राएं अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। साइकिल मिलने से उत्साहित छात्राओं ने कहा स्कूल आने जाने में होगी सहूलियत-- साइकिल मिलने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। छात्राओं का कहना है कि निःशुल्क साइकिल मिलने की उन्हें काफी खुशी है और अब उन्हें अपने स्कूल तक आने-जाने में सहूलियत होगी। वे जल्दी स्कूल पहुंच सकेंगी, जिससे उनके समय की बचत होगी, साथ ही पढ़ाई पर उनका फोकस और मजबूत होगा।

बच्चों की मोहक मुस्कान का जादू सीएम ने बच्चों को दुलारा

बच्चों की मोहक मुस्कान से प्रसन्नचित्त मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बच्चों को दुलार करते हुए, बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता से और अपने हुनर से सुंदर चीजें बनाई थीं। मुख्यमंत्री ने इन्हें अपने हाथों में लिया और बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने इतना सुंदर कैसे बनाया। जशपुर के बच्चे डिजिटल इंडिया से भी जुड़े हैं उनके हाथ कंप्यूटर और लैपटाप के माउस पर हैं। इन पर अपने हुनर का उन्होंने कमाल भी मुख्यमंत्री को दिखाया। मुख्यमंत्री ने इन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय भी मौजूद रहीं।

विभिन्न स्टालों के सीएम साय ने किया अवलोकन

राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर लगे विभिन्न स्टालों के अवलोकन के बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी अवलोकन किया, इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमकी कौशल्यादेवी साय भी साथ थीं।

मुख्यमंत्री साय ने मां के नाम से बगिया में रोपा रुद्राक्ष का पौधा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गृहग्राम बगिया में धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ मां के सम्मान में शासकीय हाईस्कूल में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। इसके दौरान उन्होंने आशा जताई कि यह पौधे जननी और जन्मभूमि के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पौधरोपण की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि मां हमे जीवन देती है, हमारा पालन-पोषण करती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसकी सुरक्षा और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर पौधरोपण करने का आग्रह किया।

मुस्लिम समाज ने की गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर के दौरे पर रवाना हुए। रवानगी से पहले रायपुर पुलिस ग्राउंड में सीएम साय से पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग पर कहा कि हम सनातनी लोग हैं, गाय को माता मानते हैं।

मुख्यमंत्री ने दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि बगिया में शाला प्रवेषोत्सव 18 जून को होना था। लेकिन गर्मी ज्यादा थी इस वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। प्रदेश में 26 जून से स्कूल का शुभारंभ हुआ है।

रायपुर में गुरुवार को मुस्लिम महासभा सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग शामिल हुए। सम्मेलन में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और केंद्र सरकार से सभी स्लाटर हाउस को बंद करने की मांग की।

आवासन मंत्री खट्टर से मिलकर लौटे उप मुख्यमंत्री अरुण साव

कहा- 20 हजार पीएम आवास पर हुई चर्चा

रायपुर। दिल्ली दौरे से लौटे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात को लेकर कहा कि प्रदेश के विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। 20 हजार प्रधानमंत्री आवास के डीपीआर पर बात हुई। स्वच्छता के साथ पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने गंभीरता से बातों को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में जैसी रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। कई योजनाएँ तैयार हो रही हैं। जल्द ही रेल कनेक्टिविटी का छत्तीसगढ़ में विस्तार करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का रद्द होने के सिलसिले पर कहा कि देश की तुलना में प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी कम है। कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसके कारण व्यवधान आ रहे हैं। विकास का काम हो जाने पर लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी।

धान संग्रहण केंद्रों में अनियमितताओं पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। परमीसिबल लिमिट से अधिक शॉर्टेज पाया गया तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं दंतेवाड़ा विधायक भवन के जीर्णोद्धार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री साव ने पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल में दीपक बैज को कुछ दिखा था या नहीं। वे अपने सरकार की समय की बातों को जनता को बताएं।

चाहे डंडे मारो चाहे गाली दो काम तो करता है चंद्रा: भैयालाल

कोरिया। भैयालाल राजवाड़े कोरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भैयालाल की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में की जाती है। राजवाड़े अपने बयानों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। कभी विवादित बयान तो कभी चुटीले अंदाज से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। कोरिया के बुडार में शुक्रवार को बिजली सब स्टेशन का उदघाटन कार्यक्रम था। कार्यक्रम में भैयालाल राजवाड़े मुख्य अतिथि थे। विधायक जब मंच पर पहुंचे तो उन्होने अपने ही अंदाज में बैकुंठपुर के बिजली विभाग के इंजीनियर की तारीफ कर दी। तारीफ कुछ कर दी कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए।

बिजली सब स्टेशन के उदघाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा थे। मंच पर पहुंचते ही भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि पहले बिजली यहां कब आती थी किसी को पता ही नहीं चलता था। बिजली आते ही कब कट जाती थी ये भी लोगों को पता नहीं होता था। अब हालात बदल गए हैं। बिजली की तकलीफ दूर होने वाली है। लो वोल्टेज की जो शिकायत इलाके में सालों से थी वो भी दूर हो जाएगी। भैयालाल राजवाड़े ने कहा इस क्षेत्र के लोग बहुत परेशान थे। लो वोल्टेज के चलते लोग परेशान थे। बिजली आता और कितने घंटे गोल रहता है सब जानते हैं। फोन करते रहो तो चंद्रा एक ऐसा अधिकारी है जो काम करते रहता है। मेरा बहुत ज्यादा गाली खाता है। इसका ट्रांसफर भी हो गया था। मैंने सोचा कि ये चला जाएगा तो काम कौन करेगा। मैंने इसलिए इसका ट्रांसफर रुकवाया, कैंसल आर्डर भी आ गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब विधायक जी अपने बयानों से सुर्खियों में आए हैं। कई मौकों पर वो अपने अजीबो गरीब और विवादित बयानों से चर्चा का विषय बन चुके हैं। भैयालाल राजवाड़े अपने जुदा अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। विधायक बनने के बाद उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी लेकिन उनको मंत्रीमंडल में नहीं लिया गया।

केन्द्रीय रेल मंत्री को मंत्री राजवाड़े ने लिखा पत्र

कमलपुर में रेल्वे का स्टॉपेज पुनः शुरू करने का किया अनुरोध

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अम्बिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस का स्टॉपेज कमलपुर में पुनः शुरू करने का अनुरोध किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े केन्द्रीय रेल मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि अम्बिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस की अप और डाउन गाडिया़ नियमित रूप से कमलपुर रेल्वे स्टेशन में रूका करती थीं। कोविड के दौरान रेल्वे द्वारा कमलपुर स्टेशन में इस ट्रेन का स्टॉपेज अस्थाई रूप से बंद किया गया था। श्रीमती राजवाड़े ने कहा है कि उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोगों ने कमलपुर में पुनः स्टॉपेज शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कमलपुर के आस-पास लगभग 3500 लोगों की आबादी है, जो इस स्टॉपेज के माध्यम से रेल सुविधाओं का उपयोग करती हैं। इसके अलावा इस स्टेशन के पास ग्राम सिलफिली में बड़ी सब्जी मंडी भी है। कमलपुर स्टेशन से अम्बिकापुर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है।

श्रीमती राजवाड़े ने यह भी अवगत कराया कि रोजाना बड़ी संख्या में अम्बिकापुर से विश्रामपुर के लिए लोगों का आना-जाना लगा रहता है। अतः कमलपुर में स्टॉपेज पुनः शुरू करने से कमलपुर और आस-पास के गांव सहित अम्बिकापुर और विश्रामपुर से आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

रेडी टू ईट की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है

■ **सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना : लक्ष्मी राजवाड़े**

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महिलाओं को लेकर सरकार के मुख्य उद्देश्य और रेडी टू ईट समेत अन्य जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रमुख उद्देश्य ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए विभाग द्वारा अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा रेडी टू ईट सप्लाई का काम महिलाओं को वापस सौंपा जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार और आर्थिक स्थिरता मिल सके।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि रेडी टू ईट की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और सप्लाई चैन सुचारू रूप से चल रही हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा महिलाओं का हक छीन कर उनका यह काम एनजीओ को दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद फिर से महिलाओं को इस काम में लगाया जा रहा है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने यह भी स्पष्ट किया कि बीज निगम के 162 करोड़ रुपये के पेमेंट को लेकर कोई भी अवरोध नहीं है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।

तीन ट्रक धड़ा धड़ आपस में भिड़े 10 किलोमीटर लगा लंबा जाम

कवर्धा। रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 30 में एक्सीडेंट के बाद 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। एक्सीडेंट वाली जगह के दोनों ओर छोटे बड़े लंबे वाहन फंसे हुए हैं। जाम के कारण सैकड़ों ट्रक, बस, कार, छोटी वाहन फंसे हुए हैं। कबीरधाम जिले से होकर गुजरने वाली रायपुर- जबलपुर नेशनल हाईवे 30 के चिल्फी थाना अंतर्गत ग्राम अकलहरिया के पास तेज बारिश के कारण सुबह 10 बजे दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार तीसरी ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकरा गई, जिससे नेशनल हाईवे सड़क में पुरी तरह जाम हो गया। चिल्फी थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर ने कहा दो ट्रक की भिड़ंत हुई थी। इसी दौरान तीसरी ट्रक भी जा भिड़ी इस जिससे ग्राम अकलहरिया के पास सड़क पर जाम की स्थिति हो गई है। पुलिस की टीम सड़क से ट्रक को हटाने का प्रयास कर रही है। जल्द ही रास्ता क्लियर कर लिया जाएगा।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
MAHANADI PROJECT, RAIPUR (CHHATTISGARH)

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
(First Call)

System Tender No. 155638/ NIT No.: 02/SAC/24-25 Dated: 02.07.2024
Online Tenders are invited for the following work up to 23.07.2024 at 17.30 Hours.
Name of work - Construction of Gujra Stopdam in Block Arang, District Raipur.
Probable Amount of Contract: - **Rs. 324.83 Lakhs**
(As per S.O.R dated 01.08.2010 and amended upto dated 22.08.2022).

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal **(https://eproc.cgstate.gov.in)from Date 09.07.2024, at 17.31 Hours. (IST) onwards.**

NOTE: All eligible/intrested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e- procurement portal **(https://eproc.cgstate.gov.in)** and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor/Supplier Registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

Executive Engineer
Water Management Division No. 1, Raipur
For, Chief Engineer, Mahanadi Project
Raipur (C.G.)

जी-242500830/8

अकलतरा-नैला सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का कार्य से यातायात प्रभावित

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है 7 इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अकलतराङ्गनैला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी व ऑटो सिग्नलिंग का कार्य 12 से 16 जुलाई तक किया जायेगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों के परिचालन में गतिशीलता आयेगी। प्रभावित होने वाली गाडियों का विवरण इस प्रकार है-

रद्द होने वाली एक्सप्रेस गाडियां

11 से 15 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 11, 12, 14, 15 एवं 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 12070 गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 12, 13, 15, 16 एवं 17 जुलाई' तक गाड़ी संख्या

12069 रायगढ़-गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 13 जुलाई' को गाड़ी संख्या 18249 रायपुर-कोरबा, हसदेव एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 14 जुलाई' को गाड़ी संख्या 18250 कोरबा- रायपुर, हसदेव एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 14 जुलाई' को गाड़ी संख्या 18251 रायपुर-कोरबा, हसदेव एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 15 जुलाई' को गाड़ी संख्या 18252 कोरबा- रायपुर, हसदेव एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

पैसेंजर गाड़ियां

12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08738 बिलासपुर- रायगढ़ मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 11 से 15 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08732 बिलासपुर-कोरबा मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08731 कोरबा-बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 11 से 15 जुलाई'तक गाड़ी संख्या 08280 रायपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08279 कोरबा-रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08210 बिलासपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 11 से 15 जुलाई'तक गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 13 एवं 14 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08264 बिलासपुर-टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 13 एवं 14 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 08263 टिटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

गंतव्य/प्रस्थान बिन्दु से पहले समाप्त एवं शुरू की जाने वाली गाडियां

11 से 15 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 18518 विशाखापट्टनम-कोरबा एक्सप्रेस बिलासपुर में समाप्त होगी । यह गाड़ी बिलासपुर-कोरबा के मध्य रद्द रहेगी । 12 से 16 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 18517 कोरबा-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस बिलासपुर से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होगी । यह गाड़ी कोरबा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी । 10 से 15 जुलाई'तक गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस बिलासपुर में समाप्त होगी । यह गाड़ी बिलासपुर-टाटानगर के मध्य रद्द रहेगी । 12 से 17 जुलाई' तक गाड़ी संख्या 18110 नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस बिलासपुर से नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी के लिए रवाना होगी । यह गाड़ी टाटानगर-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी ।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in
--000--

स. क्र.	कार्य का नाम	निविदा सूचना क्र/ सिस्टम निविदा क्र./ दिनांक	अनुमानित लागत	निविदाकार की योग्यता
1	धमतरी जिले के विकासखंड धमतरी की महानदी परियोजना अंतर्गत महानदी मुख्य नहर के आर.डी. 390 मी. से 10000 मी. तक लाईनिंग एवं मरम्मत कार्य।	03/व.ले.लि./2024-25/ 155167 दिनांक-25.06.2024 (द्वितीय आमंत्रण)	रु. 453.48 लाख	PWD से पंजीकृत 'बी' वर्ग एवं उससे ऊपर श्रेणी के ठेकेदार
2	महानदी मुख्य नहर के वितरक शाखा क्र. 4 के आरडी 0 मी से 6000 मी. तक तथा चोरभट्टी माईनर का लाईनिंग कार्य। तक लाईनिंग एवं मरम्मत कार्य।	04/व.ले.लि./2024-25/ 155168 दिनांक-25.06.2024 (पंचम आमंत्रण)	रु. 261.14 लाख	PWD से पंजीकृत 'बी' वर्ग एवं उससे ऊपर श्रेणी के ठेकेदार

Date-Time Detail(s)
(Tender Time Schedule)

1. **Bid Start Date and time: 02.07.2024, 17:31 Hours**
   The date and time from which bidders start preparation) (
   Submission of their bid response, before this bidder's action will not be allowed)
2. **Bid Due Date and time: 12.07.2024, 17:30 Hours**
   (The last date & time for submission of bid response, after which no bids can be submitted.)
3. **Bid Open Start Date and time: 15.07.2024, 11:30 Hours.**
   (The Date of opening of Envelope A & B online)

The bids of the contractors have to be digitally signed by the Digital Certificate of the contractor before submitting the bids online.

Any clarification / doubts regarding the process of eProcurement System (EPS) may be obtained from EPS Help Desk Toll free 1800 258 2502 or on email helpdesk.eproc@cgswan.gov.in.

All the contractors are required to submit Envelope 'A' online only.

Physical submission of Envelope 'A' shall only be done by the tenderer whose financial bid is found the lowest in the manner described in para 2.1.5 (A)

कार्यपालन अभियंता
म.ज.प. बांध संभाग क्र. 2, रूद्री
कृते मुख्य अभियंता महानदी परियोजना
जल संसाधन विभाग, रायपुर, (छ.ग.)

जी-242500774/11

पार्टियां अल्पसंख्यकों को वोट बैंक न समझें

योगेन्द्र योगी

देश में अल्पसंख्यकों के विकास की बजाय भावनात्मक मुद्दों पर बरगला कर उनके दोहन का खेल जारी है। राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की फसल से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अल्पसंख्यकों का अधिक हितैषी साबित करने के लिए गैर-भाजपा राजनीतिक दलों में कभी खत्म नहीं होने वाली चुनावी प्रतिस्पर्धा जारी है। इसका मंच चाहे चुनावी सभाएं हो या संसद के दोनों सदन। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक वोट बैंक को रिझाने के प्रयास में भाजपा पर देशभक्त अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और सिख लोगों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाते हैं। जबकि अल्पसंख्यक हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। अल्पसंख्यक देश के साथ पत्थर की तरह खड़े हैं, देशभक्त हैं और आप सबके खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यकों ने देश के साथ-साथ संविधान की भी रक्षा की है। राहुल गांधी का यह बयान महज एक चुनावी बयान से अधिक कुछ नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल किया गया हो। चुनावी सभाएं हों या संसद, मौके-बेमौकों पर अल्पसंख्यक की हिमायत करने का कांग्रेस और दूसरे गैर-भाजपा दल कोई मौका नहीं छोड़ते। अल्पसंख्यकों की पैरवी करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी ने यह खुलासा कभी नहीं किया कि आजादी के करीब 60 साल तक कांग्रेस का शासन केंद्र और ज्यादातर राज्यों में रहने के बावजूद अल्पसंख्यक बुनियादी सुविधाओं और देश की विकास की मुख्यधारा से दूर क्यों हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर हाय-तौबा मचाने वाली कांग्रेस ने कांग्रेसशासित राज्यों में उनकी भलाई के लिए कौन से प्रयास किए। इसके अलावा केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों से कौनसा भेदभाव किया गया है। इसका भी खुलासा कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। यह सही है कि भाजपा ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पार्टी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया, किन्तु यह भाजपा का आंतरिक मामला है। सरकारी स्तर पर भाजपा के मुसलमानों से भेदभाव का एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है। जो योजनाएं देश या राज्यों के स्तर पर भाजपा सरकारों ने लागू कि उनमें सभी को पात्रता के आधार पर सुविधाएं दी गई हैं। जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर कोई अंतर नहीं रखा गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार साल 2014 से देश में पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लगभग 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से खासकर मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोडने् की संख्या कम हुई है। 2014 से पहले मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोडने् की संख्या 70 प्रतिशत थी जो अब घट कर 30 प्रतिशत से भी कम हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा 'सीखो और कमाओ' योजना शुरू की गई। इसी योजना के तहत इस साल यानी 2022 में लगभग 8 लाख महिला को लाभ पहुंचा है। देश के किसी भी भाजपाशासित राज्य में एक भी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया सिवाय बाबरी मस्जिद के, जिसका फैसला भी कानून के दायरे में हुआ। मथुरा में ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि विवाद और वाराणसी में ज्ञानव्यापी विवाद अदालत में विचाराधीन है। जबकि पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मुसलमानों को देशभक्त बताने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस पर भी कभी प्रतिक्रिया नहीं दी कि केंद्र में मोदी सरकार सरकार आने के बाद देश में आतंकियों द्वारा किए जाने वाले बम धमाके कैसे रुक गए। इन बम धमाकों के आरोपियों के लगभग सभी नाम मुस्लिम समुदाय से ही क्यों आए। इसके अलावा देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर लगाम कैसे लग गई। भाजपा को चाहिए मुसलमानों को भी पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी दे ताकि दूसरे दलों के अल्पसंख्यकों के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति पर अंकुश लगाया जा सके।

संसद का पहला सत्र और भविष्य के संकेत

जयसिंह रावत

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास कराने के साथ ही संसद की कार्यवाही 3 जुलाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। आम चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा की कार्यवाही 24 जून को शुरू हुई थी जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तर के बाद 2 जुलाई को तथा राज्यसभा का 264 वां सत्र प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद 3 जुलाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के इस सत्र में और खासकर लोकसभा में जिस तरह का संग्राम हुआ वह भविष्य के संसदीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी बजा गया।

दरअसल, लोकसभा में एनडीए और इंडिया नाम के दो गठबंधन पक्ष और विपक्ष के जैसे आचरण करने के बजाय दो घोर शत्रुओं का जैसा आचरण कर रहे थे और पीठासीन अधिकारी पंच परमेश्वर की भूमिका नहीं निभा रहे थे। जिम्मेदार नेता संसदीय आचरण और परम्पराओं को भूलकर राष्ट्रहित की बातें कम और एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत जहर ज्यादा उगल रहे थे, इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों हाथों से ताली बजने के कारण संसद में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है जो आने वाले सत्रों के लिए बहुत बुरा संकेत है।

संसद में टकराव स्पीकर के चुनाव को लेकर ही शुरू हो गया था। सत्ता पक्ष विपक्ष को यह संदेश देना चाहता था कि तुम चाहे हमारा आधार और लोकप्रियता घटने का जितना भी प्रचार करो और बहुमत न मिलने का चाहे जितना भी ढोल क्यों न पीट लो मगर सरकार हमारी ही बन गई और तुम सब मिलकर भी एक अकेली भाजपा के बराबर नहीं पहुंच सके।

सत्ता पक्ष पहले ही मंत्रियों को पुराने विभाग देकर संदेश दे चुका था कि सबकुछ वही है और सरकार का इकबाल उतना ही बुलंद है, इसलिए स्पीकर भी वही रहेंगे जो कि मोदी-2 में थे। लेकिन विपक्ष सत्रहवीं लोकसभा के कटु अनुभव नहीं भूला था।

पिछली बार विपक्ष के जो 140 सांसद संसद से निलंबित किए गए उनमें 100 सांसद लोकसभा के थे। यही नहीं विपक्ष को स्पीकर ओम बिड़ला से एक नहीं बल्कि अनेक शिकायतें थीं इसलिए विपक्ष का ओम बिड़ला के नाम से बिदकना स्वाभाविक ही था। लेकिन टकराव की असली वजह इस बार विपक्ष के और ताकतवर बन कर उभरने की तथा सत्ता पक्ष और खासकर भाजपा के कमजोर होने की थी, इसलिए विपक्ष भी सत्ता पक्ष को अपनी ताकत का अहसास दिलाने के लिए डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ा रहा। बहरहाल लोकसभा में महज ध्वनिमत से ओम बिड़ला स्पीकर चुन लिए गए।

चूंकि विपक्षी इंडिया खेमे ने आम चुनावों के दौरान संविधान को खतरे का मुद्दा बनाया था और उसे कुछ हद तक इसका लाभ भी मिला था, इसलिये विपक्षी सदस्यों ने उस मुद्दे को जिन्दा रखने के लिए संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। जो कि सत्ता पक्ष को नागवांर गुजरी। इसलिये उसने भी राष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारियों के मार्फत 1975 में लगी इमरजेंसी की याद विपक्ष को दिला दी। इसने आग में घी डालने का काम किया।

सर्वविदित् है कि राष्ट्रपति का भाषण कैबिनेट द्वारा तैयार होता है और उसी की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाता है। लेकिन स्पीकर या राज्यसभा के सभापति की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। लोकसभा में स्पीकर का एक पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेकर इमरजेंसी का निन्दा प्रस्ताव पढ़ना विपक्ष और खास कर विपक्ष के सबसे बड़े दल को नागवार गुजरना स्वाभाविक ही था। बात यहीं समाप्त नहीं हुई।

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण प्रधानमंत्री को उकसाने के लिए काफी था और उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिस तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी पर केन्द्रित किया उसका जवाब उन्हें तत्काल ही सदन में भारी हूटिंग से मिल गया।

पिछली बार विपक्ष बहुत कमजोर और बंटा हुआ था इसलिए अक्सर सत्ता पक्ष के भारी बहुमत की हूटिंग से विपक्ष के नेताओं की आवाजें दब जाया करतीं थीं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने अपनी आवाज के बढ़े हुए वॉल्यूम का अहसास जानबूझ कर प्रधानमंत्री को दिलाया। हालांकि इसका जवाब भी विपक्ष को आने वाले सत्रों में अवश्य मिलेगा।

संसद का महौल बिगाड़ने के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही पीठासीन अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण रवैया भी जिम्मेदार रहा है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने पहले ही सत्र में संकेत दे दिया कि वे न तो बदलने वाले हैं और लोकतंत्र से ज्यादा उनकी निष्ठा पद का सुख प्रदान कराने वालों के प्रति है।

बीते सत्र के दौरान न तो विपक्ष ने सदन के नेता प्रधानमंत्री का लिहाज किया और ना ही नेता विपक्ष के पद का लिहाज किया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष के भाषण के रिकॉर्ड में जिस तरह काटपीट हुई वह नेता प्रतिपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ही था।

संसद में भारी हंगामें और पक्ष-विपक्ष की बीच बहुत तीखी तकरार के कई मौके आ चुके हैं। लेकिन ऐसी नौबत शायद ही पहले कभी आई हो। राज्य विधानसभाओं में पक्ष विपक्ष की दुश्मनी के चलते अनेक बार हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। 1 जनवरी 1988 को तमिलनाडु विधानसभा में जानकी रामचंद्रन ने विश्वास मत के लिए विशेष सत्र बुलाया था। अपने पति एमजीआर के निधन के बाद वह मुख्यमंत्री बनीं थीं। लेकिन ज्यादातर विधायक जयललिता के साथ थे। इस दौरान सियासी गठजोड़ के बीच विधानसभा की बैठक में माइक और जूते चले। सदन में लाठीचार्ज भी करना पड़ा।

इसी तरह 25 मार्च 1989 तमिलनाडु विधानसभा में ही बजट पेश करने के दौरान दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान जयललिता की साड़ी फाड़ने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 22 अक्टूबर 1997 में दंगा भड़क गया, जिसमें विधायकों ने एक-दूसरे पर फेंकने के लिए माइक्रोफोन, कुर्सियां और अन्य सामान उठा लिया। सुरक्षाकर्मियों ने अध्यक्ष की ढाल के रूप में डेस्क के ऊपरी हिस्से को उखाड़ दिया। विधायकों के बीच हुई हिंसा इस कदर बढ़ी जिसमें स्पीकर समेत कई विधायक घायल भी हुए।

महाराष्ट्र विधानसभा में 10 नवंबर 2009 को सपा के विधायक अबु आजमी ने हिंदी में शपथ ली तो एमएनएस के चार विधायक हिंसक हो गए। इसके बाद चार साल तक इन विधायकों को सस्पेंड किया गया। केरल विधानसभा में 13 मार्च 2015 केरल विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए हाथपाई शुरु कर दी। इस दौरान दो विधायक घायल हो गए। अगर संसद में दोनों पक्षों का नजरिया नहीं बदला तो राज्य विधान सभाओं में हुई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की नौबत संसद में भी आ सकती है।

संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले विवादास्पद विषयों पर भी बहस मर्यादा का उल्लंघन न करे इसलिये संसद द्वारा ही सदस्यों के लिये आचार संहिता तैयार की जाती है। इसीलिये कहा जाता है कि संसद किसी की इच्छा या राजनीतिक सहूलियत से नहीं बल्कि नियमों से चलती है। कुछ स्थापित संसदीय रीति-रिवाज, परंपराएं, शिष्टाचार और नियम हैं जिनका पालन सदस्यों को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह करना आवश्यक होता है। ये न केवल संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों और पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों और टिप्पणियों पर आधारित होते हैं बल्कि संसद की पिछली प्रथाओं, परंपराओं और उदाहरणों पर भी आधारित होते हैं, जिन्हें सदस्य संसद में अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं।

ये सभी वही हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से संसदीय शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। सदन को अपने सदस्यों को सदन में या बाहर उनके कदाचार के लिए दंडित करने का अधिकार है। सदस्यों द्वारा किए गए कदाचार या अवमानना के मामलों में, सदन चेतावनी, फटकार, सदन से निकासी, सदन की सेवा से निलंबन, कारावास और सदन से निष्कासन के रूप में दंड दे सकता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

हंसोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

इस प्रकार मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो नाद विद्यमान रहता है, वह शुद्ध स्फटिकमणि सदृश ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते हैं।

इस प्रकार इस (अजपा मंत्र) का ऋषि हंस (प्रत्यगात्मा) है, अव्यक्त गायत्री छन्द है और देवता परमहंस (परमात्मा) है। हं बीज और सः शक्ति है। सोऽहम् कीलक है।

इस प्रकार इन षट् संख्यकों द्वारा एक अहोरात्र (अर्थात् 24 घंटों) में इक्कीस हजार छः सौ श्वास लिए जाते हैं। (अथवा गणेश आदि 6 देवताओं द्वारा दिन-रात्रि में 21,600 बार सोऽहम् मंत्र का जप किया जाता है।) सूर्याय सोमाय निरञ्जनाय निराभासाय अतनु सूक्ष्म प्रचोदयात् इति अग्नीषोमाभ्यां वौषट् इस मंत्र को जपते हुए हृदयादि अंगन्यास तथा करन्यास करे। तत्पश्चात् हृदय स्थित अष्टदल कमल में हंस (प्रत्यगात्मा) का ध्यान करे।

अग्नि और सोम उस (हंस) के पक्ष (पंख) हैं, ओंकार सिर, बिन्दु सहित उकार (हंस का) तृतीय नेत्र है, मुख रुद्र है, दोनों चरण रुद्राणी हैं। इस प्रकार सगुण निर्गुण भेद से दो प्रकार से कण्ठ से नाद करते हुए, हंस रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अतः नाद द्वारा ध्यान करने पर साधक को उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति को अजपोपसंहार कहते हैं। समस्त भाव हंस के अधीन हो जाते हैं, अतः साधक मन में स्थित रहते हुए हंस का चिन्तन करता है। इसके (सोऽहम् मंत्र के) दस कोटि जप कर लेने पर साधक को नाद का अनुभव होता है। वह नाद दस प्रकार का होता है। प्रथम-चिणी, द्वितीय-चिञ्चिणी, तृतीय-घण्टनाद, चतुर्थ-शंखनाद, पंचम-तंत्री, षष्ठ-तालनाद, सप्तम-वेणुनाद, अष्टम-मृदङ्गनाद, नवम-भेरीनाद और दशम-मेघनाद होता है। इनमें से नौ का परित्याग करके दसवें नाद का अभ्यास करना चाहिए।

क्रमशः ...

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के सच्चे महानायक

ललित गर्ग

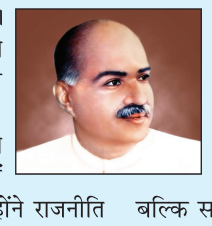

भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक चैतन्य महापुरुषों ने देश की माटी को प्रणम्य बनाने एवं कालखंड को अमरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं कीर्तिवान महान पुरुषों में भारत केसरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सश्रद्धा एवं गर्व से लिया जाता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में हुआ था। वे बैरिस्टर और शिक्षाविद थे तो कुशल समाज-राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि, नेहरू-लियाकत समझौते के विरोध में मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1980 में यही भारतीय जनता पार्टी बन गई। वे भारत को एक हिन्दू राष्ट्र एवं स्व-संस्कृति के अनुरूप विकसित होते हुए देखना चाहते थे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। सचमुच! वह कर्मयोद्धा कर्म करते-करते कृतकाम हो गया।

डॉ. मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉ. मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक, सच्चे राष्ट्रभक्त और सिद्धान्तवादी थे। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी हिन्दुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबन्धन का निर्माण किया। इस सरकार में वे वित्तमन्त्री बने। इसी समय वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिन्दू महासभा में सम्मिलित हुए। उनका मानना था कि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति को भुला देता है, वह राष्ट्र वास्तव में जीवित एवं जागृत राष्ट्र नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग की राजनीति से न केवल बंगाल बल्कि समूचे देश का वातावरण दूषित हो रहा था। वहाँ साम्प्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। साम्प्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिन्दुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनैतिक दलों के छोटे-बड़े सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया।

डॉ. मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं। इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि विभाजन सम्बन्धी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से थी। वे मानते थे कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं। हममें कोई अन्तर नहीं है। हम सब एक ही रक्त के हैं। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। परन्तु उनके इन विचारों को अन्य राजनैतिक दल के तत्कालीन नेताओं ने अन्यथा रूप से प्रचारित-प्रसारित किया। भारत का जब पहला मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के नेतृत्व गठित हुआ तब महात्मा गाँधी और सरदार पटेल के अनुरोध पर डॉ. मुखर्जी पहले मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए और उन्हें उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मेदार पद सौंपा गया।

नेपाल में एक बार फिर सत्ता संघर्ष

महेंद्र वेद

नेपाल में हिमालय और भगवान पशुपतिनाथ को शाश्वत माना जाता है। लेकिन न तो हिमालय की मौजूदगी और न ही भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित कर सका है। लालची नेताओं के आपसी संघर्ष ने एक और सरकार को खतरे में डाल दिया है।

राजशाही के खत्म होने और नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड की 13वीं सरकार पर विद्रोह का खतरा मंडरा रहा है। उप प्रधानमंत्री और बुनियादी संरचना व परिवहन मंत्री रघुबीर महासेठ ने प्रधानमंत्री दहल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल के समर्थन वापस लेने के बाद जब 20 मई को दहल ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल किया था, तो 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में उन्हें 157 वोट मिले थे। अब यूएमएल के समर्थन वापस लेने से उनमें से 77 वोट घट गए हैं। हालांकि दहल ने इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया है और अब वह नेशनल असेंबली में विश्वास मत की मांग करेंगे। हालांकि वह पहले तीन बार विश्वास मत हासिल कर चुके हैं, लेकिन नेपाल के सियासी भंवर में यह पर्याप्त नहीं है। वास्तव में 2008 के बाद से इस हिमालयी देश में सभी सरकारें दो या दो से अधिक पार्टियों की गठबंधन वाली रही हैं, जिनमें सहयोगी और विरोधी दल बारी-बारी से अपनी स्थिति बदलते रहे हैं।

एक बार फिर सियासी घमासान मचा है। 69 वर्षीय दहल, जो तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, के अलावा 72 वर्षीय खड्ग प्रसाद शर्मा ओली दो बार, तो 78 वर्षीय शेर बहादुर देउबा रिकॉर्ड पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बहुमत दिखाने के लिए विश्वास मत हासिल करने की खातिर संविधान के तहत दहल को 30 दिन का समय मिलेगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी, जिससे स्वाभाविक ही गरीब देश में आर्थिक संकट बढ़ेगा।

माओवादी सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा गठबंधन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड और सीपीएन-यूएमएल प्रमुख ओली के बीच वार्ता भी विफल हो गई है। काठमांडू से मिल रही जानकारियों के मुताबिक, दहल ने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन दिवंगत गायक फत्तेमान के एक नेपाली गीत को याद किया- येस्तो पानी हुंडो रइछा जिंदगी मा कहिले, कहिले (कभी-कभी जिंदगी ऐसे ही सामने आती है)। उन्होंने कहा, हमने बड़ी शिद्दत से साथ मिलकर काम किया, लेकिन इस बार चीजें बदल गई हैं। हमें भविष्य में भी साथ मिलकर काम करना चाहिए।

दरअसल, नेपाल एक बार फिर तीन दावेदारों के बीच सत्ता संघर्ष का साक्षी बन रहा है। दहल ने नेपाली कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन खत्म किया, जो नेपाली संसद में सबसे बड़ी पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के साथ हाथ मिलाया, जो संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दहल की पार्टी नेपाली संसद के निचले सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नेपाल इस कहावत का शानदार उदाहरण है कि राजनीति संभावनाओं का एक खेल है।

नेपाल की दो सबसे बड़ी पार्टियां, जो वैचारिक रूप से एक-दूसरे की धुर विरोधी हैं, सरकार बनाने के लिए एकजुट हो रही हैं। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) ओली के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सहमत हो गई हैं। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में दोनों की संयुक्त ताकत 167 है, जो 138 के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। इसका मतलब 18 महीने पुराने प्रचंड के शासन का?अंत?हो सकता है, जिन्होंने कभी नेपाली कांग्रेस, तो कभी सीपीएन (यूएमएल) के समर्थन से इस अवधि के दौरान तीन बार सरकार का नेतृत्व किया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने पुष्टि की कि सत्ता साझा करने पर सहमति पिछले सोमवार को ही बन गई थी। सीपीएन (यूएमएल) के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा, केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में राष्ट्रीय सर्वसम्मति वाली सरकार बनाने के लिए यूएमएल और नेपाली कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है।

नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व वित्तमंत्री प्रकाश शरण महत ने भी इसकी पुष्टि की। लिखित समझौते के अनुसार, ओली और देउबा मौजूदा प्रतिनिधि सभा के बचे हुए समय में बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। हालांकि अतीत में ओली ने दहल के लिए पद छोड़ने से इन्कार कर दिया था। नेपाल में पिछला संसदीय चुनाव नवंबर, 2022 में हुआ था, इसलिए अभी मौजूदा सदन का कार्यकाल साढ़े तीन साल बचा हुआ है। दहल के समर्थकों का कहना है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों को रोकने के लिए दहल के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। बीती एक जुलाई को दहल और गृहमंत्री रबी लामिछाने ने कहा था कि भ्रष्टाचार के बड़े घोटालों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग बनाने की तैयारी चल रही है। मंत्री ने कहा कि आयोग 25 भ्रष्टाचार संबंधी घोटालों की पहचान कर उनकी जांच करेगा। सरकार ने कहा कि यह गठबंधन सरकार को गिराने और देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश है।

पिछले चार महीनों में नेपाली सियासत में काफी उथल-पुथल देखने को मिली। एक महीने पहले संसद में भी हंगामा हुआ था, जब सदस्यों के बीच हाथापाई तक हो गई थी और मार्शलों को बीच-बचाव करना पड़ा था। इस दौरान दहल सरकार ने नई मुद्रा जारी की, जिसमें भारत से सटे इलाकों को नेपाल के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। नतीजतन भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को नेपाल को सावधान रहने का संकेत देना पड़ा। कूटनीतिक पर्यवेक्षकों ने ऐसे कदमों को बिगड़ती आर्थिक स्थिति से जनता का ध्यान हटाने के लिए उठाया गया कदम बताया। दूसरी ओर, यह विवाद चीनी प्रभाव और बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) के तहत चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के कारण भी उभरा है। नेपाली राजनेता इसका श्रेय लेना चाहते हैं और यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसी परियोजनाओं से उनके राजनीतिक आधार को बेहतर लाभ मिले। बीजिंग समर्थक ओली के प्रधानमंत्री बनने की संभावना भारत के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, और इसी तरह भारत समर्थक देउबा के उनके पीछे चलने की संभावना भी निराशाजनक है। भारत और चीन, दोनों ही इस अंतहीन सत्ता संघर्ष को देखने के लिए बाध्य हैं, जिसकी प्रतिध्वनि इस क्षेत्र की भू-राजनीति में भी दिखाई देगी।

आज का इतिहास

1906 दूसरा जिनेवा सम्मेलन पूरा हुआ।
1923 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई।
1931 बिली बर्क ने यू.एस. ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता।
1936 इंग्लैंड में मैनचेस्टर बोल्टन एंड बरी कैनाल के एक बड़े उल्लंघन ने 300 फीट पानी के झरने 300 फीट (91 मीटर) इरवेल नदी में भेजे।
1941 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा घेरने के लिए आक्रामक सेनाओं को लॉन्च किया गया था। यह आक्रमण स्मोलेंस्क शहर के पास हुआ। इसे स्मोलेंस्क की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। स्मोलेंस्क की लड़ाई के परिणामस्वरूप जर्मन जीत हुई।
1947 एके -47 राइफल का उत्पादन सोवियत संघ में शुरू हुआ। एके का मतलब है अवतोमत कलाश्निकोवा। इसे मिखाइल कलाश्निकोव ने डिजाइन किया था। यह एक अर्ध स्वचालित या स्वचालित प्रकाश भार मशीन गन है। इस बंदूक का उपयोग दुनिया के अधिकतम देशों के सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है।
1957 अल्थी गिब्सन पहले ऐसे काले टेनिस खिलाड़ी बने जिन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप जीती। वह एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी थीं और एक पेशेवर गोल्फर भी। यह दुनिया का पहला ग्रैंड स्लैम था जिसे इतिहास में किसी भी रंगीन खिलाड़ी ने जीता था।
1959 वेल्लोर अस्पताल में पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी हुयी।
1961 मोजाम्बिक के निकट पुर्तगाल के जहाज में विस्फोट से 300 लोग मरे।
1962 संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागरिक उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियरेक्सप्लोसियन के उपयोग की जांच करने के लिए एक कार्यक्रम, ऑपरेशन प्लोवशेयर के भाग के रूप में सेडान परमाणु परीक्षण किया।
1964 मलावी ने यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। मलावी को पहले न्यासालैंड कहा जाता था। यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। यह एक महाद्वीप का देश है जो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह सबसे कम विकसित देशों में से एक है।
1966 मलावी एक गणतंत्र देश बन गया। देश ने अपने नए संविधान को अपनाया ठ इस प्रकार गणतंत्र राष्ट्रों के क्लब में शामिल हो गए। हेस्टिंग्स बांदा मलावी के पहले राष्ट्रपति बने।

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रचनात्मक सहयोग जरूरी

कृष्णमोहन झा

17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके ओम बिरला जिस दिन से 18 वीं लोकसभा अध्यक्ष चुने गए उसी दिन से लोकसभा की कार्यवाही में गतिरोध की शुरुआत हो गई। उल्लेखनीय है कि उन्हें लगातार दूसरी बार सदन के अध्यक्ष की आसंदी पर आसीन होने का सौभाग्य मिला है । सत्ता पक्ष द्वारा सदन का उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिए जाने की मांग ठुकरा दिए जाने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन संभव नहीं हो सका। उनके विरोध में विपक्ष ने के आर सुरेश को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में उतारा था लेकिन सत्तारूढ एनडीए का संख्या बल विपक्ष से अधिक होने के कारण 18 वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ओम बिरला को ध्वनिमत से अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के मुख्य नेताओं ने ओम बिरला को सदन का अध्यक्ष चुने पर बधाई और शुभकामनाएं दी लेकिन अध्यक्ष की आसंदी पर आसीन होने के कुछ ही देर बाद जब ओम बिरला ने देश में 25 जून 1975 को लागू किए आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए जब उसके विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पेश किया तो सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन इस हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी । सदन में दूसरी बार टकराव की स्थिति तब बनी जब कांग्रेस की टिकट पर निर्वाचित शशि थरूर ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा। इस पर लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि आप संविधान की ही शपथ ले रहे हैं। अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर हरियाणा के पांच बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खड़े होकर पूछा कि इसमें आपत्ति क्या है। लोकसभा अध्यक्ष को दीपेंद्र हुड्डा की यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने हुड्डा से तल्ख लहजे में कहा,मुझे सलाह मत दो बैठ जाओ। विपक्ष को पांच बार के सांसद के प्रति यह तल्खी पसंद नहीं आई । सदन में आमतौर पर शांत और संयत रहने वाले एक वरिष्ठ सांसद को इस तरह डपटने के लिए सदन के बाहर भी लोकसभा के अध्यक्ष की आलोचना की गई ।

18 वीं लोकसभा के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गत शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के के पूर्व ही जब विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर चर्चा की ?मांग की तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उसे परंपरा के विरुद्ध मानते हुए अस्वीकार कर दिया। विपक्ष ने अपनी मांग पर अड़ते हुए जब हंगामा शुरू कर दिया तो अध्यक्ष ने फिर सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रारंभ बहस में में वह भाग लेने के लिए विपक्ष तैयार तो हुआ परंतु सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में बार बार सत्ता पक्ष को उत्तेजित करने की मंशा स्पष्ट महसूस की जा सकती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि

राहुल गांधी की बहुत सी टिप्पणियां केवल अनुमान पर आधारित थीं जिनके कोई विश्वसनीय प्रमाण उनके पास नहीं थे। किसानों की उपज की एम एस पी पर खरीद और शहीद अग्निवीरों को मुआवजा के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा उस पर तत्काल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब वस्तुस्थिति से अवगत कराया तो राहुल गांधी अपनी बात के समर्थन में कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। हिंदू और हिंदुत्व के संबंध में उन्होंने जो तर्क दिए उसमें वे स्वयं फंसते नजर आए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इन आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से विलोपित कर दिया परंतु राहुल गांधी अभी भी अपनी उन आपत्तिजनक टिप्पणियों पर खेद व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि वे तो यह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ग़लत नहीं कहा है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब अपना भाषण प्रारंभ किया तभी विपक्ष ने टोका-टाकी और नारेबाजी शुरू कर दी जो पूरे भाषण के दौरान जारी रही। विपक्ष से यह अपेक्षा स्वाभाविक थी कि जब उसके सभी सदस्यों के विचार सत्ता पक्ष द्वारा सुने जा चुके थे तो विपक्ष को भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सदन की गरिमा को बिना आंच पहुंचाए प्रधानमंत्री के विचार सुनने चाहिए थे लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी और शोरगुल का सिलसिला इसलिए जारी रखा ताकि प्रधानमंत्री अपना भाषण पूरा नहीं कर पाएं। आखिरकार प्रधानमंत्री ने उसी शोरगुल में अपना भाषण पूरा किया उसके बाद सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्य सभा में भी जब प्रधानमंत्री बहस का उत्तर दे रहे थे तब भी विपक्ष लगातार नारेबाजी और शोरगुल करता रहा और जब उसे यह आभास हुआ कि वह अपनी नारेबाजी और शोरगुल से प्रधानमंत्री के भाषण के प्रवाह को अवरुद्ध करने में असफल हो रहा है तब वह विपक्ष के सांसदों ने सदन से वाकआउट कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री धाराप्रवाह बोलते रहे । प्रधानमंत्री का उत्तर समाप्त होने के बाद राज्य सभा ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया। विगत दिनों संसद के दोनों सदनों में सत्रावसान के पूर्व लगभग पूरे समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव देखने को मिला उसमें भविष्य में कोई कमी आने की संभावना नहीं देती। 18 वीं लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से और ताकतवर बनकर उभरा है और सत्ता पक्ष का संख्या बल गत लोकसभा की तुलना में कम हुआ है। संख्या बल में हुए इजाफे ने विपक्ष के जोश में भी इजाफा कर दिया है। उधर दूसरी ओर सत्ता पक्ष का संख्या बल भले ही कम हुआ हो लेकिन लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के लिए मिले जनादेश ने एनडीए को उत्साह से भर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े और चौंकाने वाले साहसिक फैसले लेकर विपक्ष को निस्तेज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी । इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मोदी सरकार के सामने तीसरे कार्यकाल में पहले से अधिक चुनौतियां होंगी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सभी घटक दलों को एकजुट रखने की होगी।

विपक्ष की आवाज का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत

विश्वनाथ सचदेव

आखिरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता की आवाज सुनाई दे ही गई। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले संसद में बोले नहीं, पर तब वह कांग्रेस के एक नेता के रूप में ही बोलते थे, पर अब उनकी आवाज पूरे विपक्ष की आवाज मानी जाएगी और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, लोकतांत्रिक परंपराओं का तकाजा है कि वे नेता प्रतिपक्ष की बात ध्यान से सुनें, सोमवार को लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण को इस दृष्टि से देखा-सुना जाएगा। पिछले दस साल में हमारी लोकसभा में प्रतिपक्ष तो था पर नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष किसी को नहीं चुना जा

सकता था। चुनावों में भाजपा को मिली सफलता इतनी %भारी% थी कि विपक्ष की आवाज दब-सी गई थी। पर इस बार ऐसा नहीं है। आज देश में एक मिली-जुली सरकार है। भाजपा को सबसे बड़े दल के रूप में चुनने वाले मतदाता ने कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी हैं कि उसका नेता सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम कर सके। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष का यह संतुलन जनतंत्र को मजबूत बनाने वाला है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में हुई बहस से देश को ऐसी ही उम्मीद है। चूंकि लोकसभा में दस साल बाद कोई नेता प्रतिपक्ष बना है इसलिए यह उत्सुकता होनी स्वाभाविक थी कि राहुल गांधी सदन में क्या और कैसे कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात लगभग सौ मिनट में पूरी की और ऐसे अनेक मुद्दे उठाए जो मतदाता को सीधा प्रभावित करते हैं। यह कतई जरूरी नहीं है कि उनकी बातों से सहमत हुआ ही जाए, पर इतना तो स्वीकारना ही होगा कि राहुल गांधी ने अपनी बात मजबूती से देश के सामने रखी है। यह भी मांग की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष के भाषण में कही गई बातों को सत्यापित कराया जाए। जनतंत्र में प्रतिपक्ष का काम सत्ता के क्रिया-कलाप पर नजर रखने का होता है। कमजोर प्रतिपक्ष यह काम आशा और आवश्यकता के अनुरूप नहीं कर सकता। इसीलिए यह कामना की जाती है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में एक संतुलित समीकरण बने। इस संतुलन में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष जागरूक हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करे, यह सफल जनतंत्र की एक महत्वपूर्ण शर्त है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के दौरान विपक्ष की सजगता और सक्रियता के संकेत मिले हैं। पर यहीं यह भी जरूरी है कि सदन में जो कुछ कहा जाए, वह ठोस आधार पर हो। विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी तैयारी के साथ सदन में आए, अधूरे तर्क और अनावश्यक नाटकीयता से बचा जाए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के पहले भाषण में कहीं-कहीं अति नाटकीयता का दिखना कोई अच्छा संकेत नहीं है।

पांच माह और 4 राज्य में विधानसभा चुनाव

हरीश गुप्ता

लोकसभा चुनाव में बहुमत से कम सीटें मिलने के बाद भाजपा नेतृत्व अगले पांच महीनों में चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में बेहद सावधानी बरत रहा है। भाजपा आलाकमान सुनिश्चित नहीं है कि चार राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे या क्रमबद्ध तरीके से। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जीतने के लिए रात-दिन एक कर रहे हैं। भाजपा अपनी जीत की लय को फिर से कायम करने के लिए इनमें से किसी भी राज्य को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। इन चुनावों के नतीजे एक महत्वपूर्ण मोड़ होंगे क्योंकि इसका असर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों और राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों पर भी पड़ेगा।

पहली चुनौती 2019 में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव 30 सितंबर, 2024 से पहले कराए जाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक अंतिम सुरक्षा मंजूरी नहीं दी है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के पास तीन राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का अधिकार है, लेकिन वह पिछले उदाहरणों का अनुकरण कर सकता है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्तूबर, 2019 को और झारखंड में उसी साल 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव कराए थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अत्याधुनिक झंडेवालान मुख्यालय पूरी तरह से बनकर तैयार है। दिल्ली मुख्यालय को पहले ही सीआईएसएफ द्वारा चौबीसों घंटे का सुरक्षा कवर दिया गया है। 'केशव कुंज' के नाम से जाना जाने वाला, उत्तर भारत का कार्यालय लगभग एक दशक से निर्माणाधीन था। इस परियोजना में लंबा समय लगा क्योंकि यह एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है।

वह भी निचले इलाके में तथा अन्य तकनीकी समस्याएं

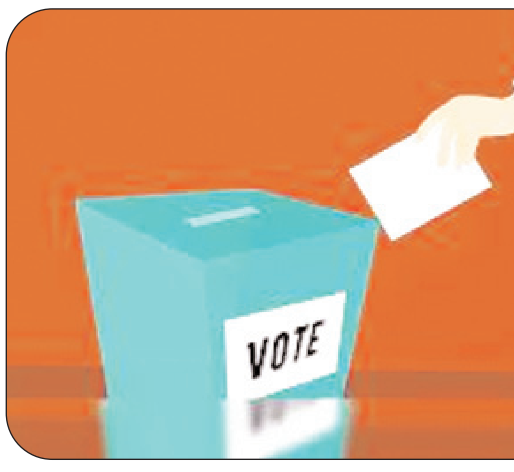

भी थीं। लेकिन इमारत अब अपने उद्घाटन समारोह का इंतजार कर रही है। यह इमारत आरएसएस के नागपुर स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय से बढ़कर होगी, जिसे 1930 के दशक में बनाया गया था। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आरएसएस अपना मुख्यालय नागपुर से दिल्ली स्थानांतरित करेगा या नहीं। केशव कुंज भवन के आधुनिक ढांचे में 12 से 16 मंजिलों के दो टावर हैं जो दो लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैले हैं जो भाजपा के नवनिर्मित राष्ट्रीय मुख्यालय से भी बड़ा है। चूंकि आरएसएस ने विशेष रूप से वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के तहत छलांग लगाई है, इसलिए यह भवन विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अपने कई प्रमुख संगठनों को भी समायोजित कर सकता है। राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के साथ ही कांग्रेस पार्टी में उत्तराधिकार का मुद्दा आखिरकार सुलझ गया है। इस घटनाक्रम ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है कि राहुल गांधी जिम्मेदारियां उठाने से भागते हैं। यह अलग बात है कि उनको अभी भी एक उत्कृष्ट सांसद का कौशल हासिल करना बाकी है। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी जल्द ही लोकसभा में पहुंच सकती हैं।

लेकिन गांधी परिवार की बागडोर औपचारिक रूप से राहुल गांधी के हाथों में चली गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश को हटाने के फैसले को पलट दिया है। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। राकांपा में भी उत्तराधिकार का मुद्दा सुलझ गया है क्योंकि सुप्रिया सुले ने बारामती लोकसभा सीट जीतकर प्रतिद्वंद्वी अजित पवार गुट को बड़े अंतर से हरा दिया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप), बीजू जनता दल (बीजद), जनता दल (यू), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और अन्य में अनिश्चितता बनी हुई है। इससे पहले, के। चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे के।टी। रामाराव को बीआरएस में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उनके भतीजे हरीश राव ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। आप में बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कई मंत्रियों के साथ शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, संदीप पाठक, गोपाल राय या यहां तक कि आतिशी मार्लेना सहित कई नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी भी यह शुरुआती दिन हैं क्योंकि केजरीवाल इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं।

ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी कई पहलों ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। वे शायद पहले कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से आशीर्वाद लिया। उन्होंने एक और पहल करते हुए राज्यों के ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रियों को उनकी सुविधानुसार समय और तारीख पर आमंत्रित किया ताकि वे उनकी समस्या को समझें और उसके अनुसार कदम उठाएं। उनकी 'लाडली बहन' योजना भी राज्यों का ध्यान खींच रही है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। अगर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मोदी सरकार में सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का उभरना दोहरी खुशी की तरह है।

विश्व कप में सफलता से बड़ा कोई ईनाम नहीं

जूलियो रिबैरो

जब हमारी भारतीय टी-20 विश्व कप टीम ने ट्रॉफी जीती तो पूरा देश एकजुट और खुश था। इसने न केवल हार के मुंह से जीत छीन ली, बल्कि अपने द्वारा खेले गए हर मैच में जीत हासिल की। पहले प्रारंभिक दौर में (एक को छोड़कर जिसे बारिश के कारण रद्द करना पड़ा), फिर दूसरे दौर व सैमीफाइनल में और फिर कैरेबियन के बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच खेला।

टूर्नामैंट की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि प्रत्येक खिलाड़ी ने अंतिम सफलता में योगदान दिया, जबकि पिछले कई टूर्नामैंटों में विभिन्न प्रारूपों में जीत या हार 1 या 2 खिलाडियों पर निर्भर थी। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर सूर्य कुमार यादव द्वारा सीमा रेखा पर लिए गए कैच ने वास्तव में मैच का रुख बदल दिया। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी 6 गेंदें शेष रहते केवल 16 रन की आवश्यकता के साथ जीत की ओर बढ़ रहे थे। यह वह कैच था जिसने दक्षिण अफ्रीका की किस्मत तय कर दी। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन अपने बेहतरीन खेल में थे। लगातार छक्के लगाते हुए गेंद को मैदान से बाहर मार रहे थे। और जैसे ही हम टैलीविजन से चिपके हुए थे, सूर्या ने डेविड मिलर का मुश्किल कैच पकड़ा। उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पूरी होशियारी से काम लेना पड़ा, ताकि गेंद के जमीन पर गिरने से पहले ही वापस कूदकर उसे पकड़ सकें।

हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आई.पी.एल. में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी, जहां उन्होंने नीता अंबानी की फ्रैंचाइजी के सबसे लोकप्रिय कप्तान रोहित शर्मा की जगह ली थी, इस साल फ्रैंचाइजी के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपना संयम और अपनी फॉर्म को फिर से हासिल किया और महत्वपूर्ण अंतिम गेम और उससे पहले के अधिकांश मैचों में चमके। अद्भुत तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह, सफेद गेंद से हमेशा की तरह किफायती और प्रभावी रहे। उन्हें एक और सिख स्पीडस्टर अर्शदीप सिंह का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने

बिल्कुल सही समय पर अपनी लय हासिल की। किंग कोहली ने उस समय अच्छा प्रदर्शन किया, जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

शनिवार को टूर्नामैंट के अंतिम मैच में उनके प्रदर्शन ने हमारी अंतिम जीत में अहम योगदान दिया। यह टी-20 क्रिकेट में उनका आखिरी मैच था। वह इस पल को कभी नहीं भूलेंगे। उनके देशवासी निश्चित रूप से इस महान क्रिकेटर के प्रति राष्ट्र के ऋण को नहीं भुला पाएंगे। मुझे गर्व है कि उन्होंने अपनी पत्नी के अभिनय करियर के सम्मान में मेरे शहर मुंबई को अपना स्थायी निवास चुना है। टी-20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले एक और दिग्गज खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा हैं। उन्होंने आई.पी.एल. मैचों में बल्ले के साथ बहुत आनंद और मनोरंजन प्रदान किया है। उन्होंने प्रत्येक खेल की शुरूआत से ही विध्वंसक की भूमिका निभाई। उनके छक्के और चौके, जिन्हें उन्होंने बेपरवाही से मारा, ने पूरे आई.पी.एल. मैचों में उनके समर्थकों को उत्साहित रखा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैमीफाइनल को छोड़कर वे विश्व कप में उतने सफल नहीं रहे, जहां रोहित कुछ रन से शतक चूक गए। मैं रोहित का मुंबई में स्वागत करता हूं, जहां वे बस गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को देखना एक और शानदार अनुभव था, न केवल स्टंप के पीछे बल्कि स्टंप के सामने भी। सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल, ने टीम को मुश्किल समय में मुश्किल हालात से निकाला। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और सभी ने इस विश्व कप टीम की सफलता में अपना योगदान दिया। यह एक बेहतरीन टीम प्रयास था, जिसका नेतृत्व एक महान कप्तान ने किया। विरोधियों के साथ सम्मान से पेश आया। छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हुए भी आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं थी।

हमारे राजनीतिक नेता इस टी-20 विश्व कप क्रिकेट टीम से कुछ सबक सीख सकते हैं। सीखने लायक महत्वपूर्ण सबक नेतृत्व के क्षेत्र में हैं। सबको साथ लेकर चलें, टीम के हर खिलाड़ी की ताकत का इस्तेमाल करें और अपने विरोधियों को कभी भी कुचलने लायक मिट्टी न समझें। यहां तक कि आर.एस.एस. के सरसंघचालक ने भी लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद यही सलाह दी थी, जहां उन्होंने अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में काफी जमीन खो दी थी। मेरे अनुसार, जब बी.सी.सी.आई. ने टीम को 125 करोड़ रुपए का ईनाम देने की घोषणा की, तो यह एक चौंकाने वाली बात थी। देश का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए विश्व कप में सफलता से बड़ा कोई ईनाम नहीं हो सकता, चाहे वह टैस्ट क्रिकेट हो, वनडे इंटरनैशनल हो या टी-20। अपने देशवासियों द्वारा उनके प्रयासों को मिलने वाला प्यार, सम्मान और मान्यता ही पुरस्कार पिरामिड का शिखर है। हमारे सामूहिक उत्साह के इस चरण में मौद्रिक पुरस्कारों का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है।

अखबारों में नकद पुरस्कार की शुरूआत को इतने भद्दे तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इसमें से निम्न कोटि के व्यवसायीकरण की बू आती है। यह भगवद् गीता की शिक्षाओं के विरुद्ध है। बिना किसी प्रतिफल की आशा के अपना कर्त्तव्य करना गीता की शिक्षाओं का मूल है। बी.सी.सी.आई. ने यह क्यों मान लिया कि खिलाड़ी सफलता की तलाश में पैसे के बारे में सोच रहे थे? बेशक, मौद्रिक रूप में एक समान पुरस्कार की हमेशा घोषणा की जाती है और इसकी अपेक्षा की जाती है। इसे बिना किसी धूमधाम के वितरित किया जा सकता था जिससे लोगों को यह न लगे कि खिलाड़ी केवल पैसे के लिए खेलते हैं। इससे कहीं बड़ी चीज है जिसके लिए वे प्रयास करते हैं वह है प्रशंसा, प्यार और सबसे बढ़कर भारत के लोगों का सम्मान।

विकास योजनाओं का हो 'सोशल ऑडिट'

रजनीश कपूर

आज से कई दशक पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार की थी कि जनता के विकास के लिए आबंटित धनराशि का जो प्रत्येक 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है, वह जमीन तक पहुंचते-पहुंचते मात्र 14 रुपए रह जाता है। 86 रुपए रास्ते में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते हैं। सारा विकास केवल कागजों पर ही होता है। परंतु बीते दशकों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बावजूद नागरिकों को कुछ सुविधाएं अवश्य मिली हैं। लेकिन बीते वर्षों में जिस तरह के विकास का जो प्रचार हुआ उसने एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कही बात याद दिला दी। इंद्र देव के कहर के कारण देश के कई भागों से काफी दर्दनाक दृश्य सामने आए। हर तरफ से तबाही के विचलित करने वाले दृश्यों को देख मन में यही सवाल उठा कि इस साल मानसून की पहली बारिश में ही जो हाल हुआ है क्या उसे वास्तव में प्राकृतिक आपदा माना जाए? क्या इस तबाही के पीछे इंसान का कोई हाथ नहीं? क्या भ्रष्ट सरकारी योजनाओं के चलते ऐसा नहीं हुआ? कब तक हम ऐसी तबाही को कुदरत का कहर मानेंगे? सरकार चाहे किसी भी दल या राज्य की क्यों न हो जनता के वोट पाने के लिए विकास कार्यों की अनेक जनोपयोगी व क्रांतिकारी योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं। ऐसी घोषणाओं को सुनकर हर कोई मानता है कि नेता जी ने एक बड़ा सपना देखा है और ये सारी योजनाएं उसी सपने को पूरा करने की तरफ एक-एक कदम है। बीते कुछ वर्षों में घोषित की गई योजनाओं में से कुछ योजनाओं का निश्चित रूप से लाभ आम आदमी को मिला है। वहीं दूसरी ओर घोषित कई योजनाएं केवल कागजों पर ही दिखाई दीं। यदि कोई प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जनता के कल्याण हेतु अनेक दकियानूसी परम्पराएं तोड़कर क्रांतिकारी योजनाएं लाते हैं, तो यह भी जरूरी है कि समय-समय पर वे इस बात का जायजा भी लेते रहें कि उनके द्वारा घोषित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कितने फीसदी हो रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी हों या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उन्हें जमीनी सच्चाई जानने के लिए गैर-पारंपरिक साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे में मौजूदा सरकारी खुफिया एजेंसियां या सूचना तंत्र उनकी सीमित मदद ही कर पाएंगे। प्रशासनिक ढांचे का अंग होने के कारण इनकी अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए देश या सूबे के मुखिया को गैर पारंपरिक 'फीड-बैक मैकेनिज्म' का सहारा लेना पड़ेगा, जैसा आज से हजारों साल पहले भारत के पहले सबसे बड़े मगध साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक किया करते थे। वह जादूगरों और बाजीगरों के वेश में अपने विश्वासपात्र लोगों को पूरे राज्य में भेजकर जमीनी हकीकत का पता लगवाते थे और उसके आधार पर अपने प्रशासनिक निर्णय लेते थे। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। यदि मोदी जी या देश के अन्य मुख्यमंत्री ऐसा कुछ करते हैं, तो उन्हें इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें उपलब्धियों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े प्रस्तुत करने वाली अफसरशाही और खुफिया तंत्र गुमराह नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास समानांतर स्रोत से सूचना पहले से ही उपलब्ध होगी। ऐसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने का यही तरीका है कि अफसरशाही के अलावा जमीनी लोगों से भी हकीकत जानने की गंभीर कोशिश की जाए। यह पहल प्रशासनिक मुखिया को ही करनी होगी, फिर वह चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री।मिसाल के तौर पर इस साल की पहली मानसून की बारिश में ही देश के कई एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, सड़कों, पुलों आदि को हुए नुकसान को गंभीरता से लेना चाहिए। विपक्ष चाहे जैसे भी हमले करे पर केंद्र व राज्य सरकार को इन दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए संबंधित राज्य सरकारों, मंत्रालयों, विभागों और अफसरशाही से समय बाधित रिपोर्ट लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, घोषित की गई विकास की योजनाओं का 'सोशल ऑडिट' भी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश के मुखिया या राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने विश्वसनीय सेवानिवृत अधिकारियों, पार्टी के समर्पित कार्यकर्त्ताओं और स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों की एक संयुक्त टीम बनानी चाहिए जो वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करे और उन तक निष्पक्ष रिपोर्ट भेजे।

स्वस्थ तन और मन के लिए याद रखें 5 नियम

हमारे शरीर की हर प्रणाली आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम इन नियमों को नियमों की तरह नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक तरीका हैं।

पूरा पोषण लेना

पोषण लेने का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय सलाद खाते रहते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से लेकर सभी विटामिन और खनिजों तक सभी पोषक तत्वों से भर दें। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा कुल कैलोरी सेवन हमारे शरीर संरचना लक्ष्यों के अनुरूप है। यह भी सुनिश्चित करते हुए कि हमारे आहार में हमारे पसंदीदा और मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे शरीर का 50-60 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना है और हमें इष्टतम स्वास्थ्य, मस्तिष्क के कार्य आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

व्यायाम और गतिविधि

सप्ताह में कम से कम 3-5 बार व्यायाम करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यायाम का कोई भी रूप जो हमारे लिए सुरक्षित है, और जिसका हम आनंद लेते हैं, हम में से अधिकांश के लिए एक अच्छी शुरूआत है। दैनिक आधार पर सक्रिय रहने और अधिक कदम (8-10' कदम) चलने के साथ इसे जोड़ना एक आदर्श संयोजन बनाता है।

इसके बाद नींद आती है

हर रात 7.5 घंटे से ज्यादा सोना अच्छा होता है। पर्याप्त नींद भी हमारी उत्पादकता में सुधार करती है और लालसा, भूख को कम करती है, सूजन और भावनात्मक प्रतिक्रिया को कम करती है।

तनाव प्रबंधन और दिमागीपन

दूसरी ओर, तनाव प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अगर तनाव को ठीक से प्रबंधित किया जाए, तो यह वास्तव में हमें बेहतर प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। याद रखें, हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसलिए, हमें सक्रिय रूप से अपने दिमाग पर काम करना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए और अपने मानसिक दोषों को कम करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान करना और कृतज्ञता जर्नलिंग रूटीन रखना इनके लिए एक गेम चेंजर है।

पर्यावरण और नियमित प्रबंधन

पर्यावरण प्रबंधन में हमारे पर्यावरण में सब कुछ शामिल है। किचन में खाने से लेकर हमारी आदतों और सोशल मीडिया पर हम लोगों को फॉलो करते हैं। क्या हम अपने आत्म-विकास और हमारे लिए महत्वपूर्ण लोगों को पर्याप्त समय दे रहे हैं? यह उस तरह के लोगों तक भी फैलता है जिनसे हम खुद को घेरते हैं। खुद से पूछने के लिए कुछ प्रश्न : क्या वे हमें प्रेरित करते हैं? क्या वे हमें और हमारे लक्ष्यों का समर्थन करते हैं? क्या वे हमें सुधारने में मदद करते हैं? क्या हमारी दिनचर्या हमें स्वस्थ बनाती है, हमें मनुष्य बनाती है या हमें अधिक उत्पादक बनाती है? मैं अत्यधिक सुबह और सोने से पहले की दिनचर्या रखने की सलाह दूंगा।

आलू का करें छिलके सहित इस्तेमाल जानिए इसके लाभ

सब्जी बनाते समय हम जब आलू का इस्तेमाल करते है, तो आमतौर पर लोग इसके छिलके निकाल कर फेंक देते है, और इसके बाद ही आलू का इस्तेमाल करते है, लेकिन क्या आप जानते हैं आलू को छिलके सहित इस्तेमाल करने के क्या सेहत लाभ मिलते हैं।

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है

आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को रेग्युलेट करने में मदद करता है।

मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है

आलू के छिलकेमेटाबॉलिज्म को भी सही रखने में मददगार होते है। इन्हें खाने से नर्व्स को मजबूती मिलती है।

एनीमिया से दूर रखता है

आलू के छिलकेमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे एनीमिया होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है।

ताकत

आलू के छिलकेमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी3 पाया जाता है, जो कि शरीर को ताकत देने का काम करता है।

फाइबर से भरपूर

हमारी डाइट में फाइबर की कुछ मात्रा जरूर शामिल होना चाहिए और आलू के छिलकेमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करते है।

लहसुन-अदरक के सेवन से रहें सेहतमंद

किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं और इसे मजबूत करने के लिए अपनी डाइट में पौष्टिक आहार व सही दिनचर्या का पालन करना भी जरूरी है। साथ ही ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने की आवश्यकता है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाए। हमारी रसोई में वे सारी औषधियां मौजूद हैं जिनके गुणों से हम अभी भी अनजान हैं।

जी हां, आप अदरक-लहसुन का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप इसके सेहत लाभ के बारे में जानते हैं? लहसुन-अदरक के सेवन से आप निरोगी काया पा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इसका सेवन कैसे करना है, इस बारे में भी हमें पता होना आवश्यक है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि केवल खाने में ही अदरक-लहसुन का सेवन काफी है लेकिन इसके अलावा भी आपको इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि खाने के पकने के दौरान इनके गुण कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस लेख में लहसुन-अदरक के फायदों व सेवन करने के सही तरीके के बारे में।

इम्यून सिस्टम को कैसे करें मजबूत?

इम्यून को मजबूत करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें। इसे खाने में पका के खाने की बजाय इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। कुछ देर इन्हें हवा लगने दें। लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल तत्व पाया जाता है। ये तत्व वायरस, बैक्टीरिया व फंगस के खिलाफ काम करते हैं। लहसुन खाने से एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी मिलता है।

लहसुन कैसे खाएं

इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। इसे आप खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। लहसुन को चबा-चबाकर खाने की बजाए इसे पानी के साथ सीधा निगल लें। इस तरह से लहसुन का सेवन करने से यह ज्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन को 25 से 30 दिन नियमित खाने के बाद आपके अंदर से लहसुन की खूशबू आना शुरू हो जाएगी तब आप समझ जाएं कि इससे अधिक आपको लहसुन का सेवन नहीं करना है।
लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होता है। इसके लिए आप इसका सेवन एकसाथ न करें व धीरे-धीरे इसकी आदत डालें। शुरुआत के समय आप लहसुन के एकदम छोटे से हिस्सा का सेवन करें, फिर इसी तरह धीरे-धीर इसे बढ़ाएं। जब आप लहसुन ले रहे हैं तो इसके साथ दही का सेवन भी करें।

अदरक

अदरक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। इसका नियमित सेवन आपको कई स्वास्थ्य लाभ देगा।

अदरक को कैसे खाएं?

अदरक को बिलकुल बारीक पीस लें व कद्दूकस करें। आपको अदरक 1 चम्मच लेना है। इसमें 6 गिलास पानी डालें। अब इसे उबलने दें। जब यह पानी 3 गिलास हो जाए तो इसे 1 कप में निकाल लें। इसे आप गुड़ या शहद के साथ भी ले सकते हैं। दिनभर में एक बार इसका सेवन करें।

क्या खाना खाने के बाद चलना सेहतमंद है?

वॉकिंग करना यानी टहलना कई वजहों से हेल्थ के लिए फायदेमंद ही है। इसस दिल स्वस्थ रहता है, कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है, मूड को बेहतर बनाता है। लेकिन क्या खाना खाने के बाद वॉकिंग करना हेल्दी है? स्टडी से पता चलता है कि यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है।

यह ब्लड शुगर को रखता है मैंटेन

डायबिटीज मैनेजमेंट में एक अहम हिस्सा आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। टाइप 2 डायबिटीज रोगियों के साथ एक कंट्रोल्ड ट्रायल में पाया गया कि जो लोग अपने मुख्य भोजन के बाद वाकिंग करते थे उनका शुगर लेवल उन रोगियों की तुलना में कम था जो दिन में सिर्फ एक बार चलते थे।

दिल के लिए है अच्छा

एक्सरसाइज आपके दिल को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर दिन चलने से आपको हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। दरअसल करेंट ओपिनियन इन कार्डियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार वाकिंग करना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लडप्रेशर के लिए फायदेमंद होता है। इस तरह खाना खाने के बाद चलना आपके दिल की देखभाल करने का एक अच्छा तरीका है।

पाचन को रखता है दुरुस्त

रिसर्च कहती है कि फिजिकल एक्टिविटी के एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के कारण खाना खाने के बाद चलना पाचन में सुधार कर सकता है। एक्सरसाइज से अपनी आंतों में फैट, लिपिड और ग्लूकोज मेटाबोलिज्म के परिवर्तनों को कम करने में मदद करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी स्थितियों को कम कर सकते हैं।

लेकिन दुष्प्रभाव भी हैं

खाने के बाद वॉकिंग करना पेट में तकलीफ की वजह भी बन सकता है। इनमें अपच, मतली, उल्टी, पेट फूलना, गैस, दस्त, और दर्द शामिल हैं। यह एक हाई कार्बोहाइड्रेट सेवन या हाल ही में खाए गए खाद्य पदार्थों के पाचन में समस्याओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए आपको चलने से 30 मिनट पहले इंतजार करना चाहिए।

चलना या वॉकिंग करना ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्या खाना खाने के बाद चलना सेहतमंद है?

जानिए मुलेठी के ये गजब के फायदे

मुलहठी स्वाद में मीठी होने के साथ-साथ कई औषधि गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से न सिर्फ खांसी में आराम मिलता है बल्कि इसके कई फायदे भी है। इसका इस्तेमाल आंखों के रोग, मुंह के रोग, गले के रोग, दमा, दिल के रोग, घाव के उपचार के लिए सदियों से किया जा रहा है आइए जानते हैं मुलहठी के गजब के फायदों के बारे में.

- अगर आप सूखी खांसी या गले की समस्याओं से परेशान हैं, तो मुलहठी आपके काम की चीज है। काली मिर्च के साथ पीस कर मुलहठी का सेवन, सूखी खांसी में तो लाभकारी है ही, साथ ही इसे चूसने या उबालकर सेवन करने से गले की खराश, दर्द आदि में भी लाभ होता है।
- मुलहठी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती है। इसे घिसकर लगाने पर चेहरे के दाग और मुंहासे ठीक हो जाते हैं, साथ ही यह आपकी त्वचा को जवा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुलहठी रक्त को भी शुद्ध करती है जिससे त्वचा की समस्याएं नहीं होती।
- दूध के साथ मुलहठी का सेवन शरीर की ताकत में वृद्धि करता है। इसके अलावा घी व शहद के साथ मुलहठी का प्रयोग करने से हृदय से संबंधित समस्याएं नहीं होती।
- मुंह में छाले हो जाने की स्थिति में मुलहठी चूसना, इसके पानी से कुल्ला करना और उसे पीना बहुत जल्दी छालों से राहत देता है। साथ ही मुलहठी आवाज को मधुर और सुरीली बनाने के लिए भी उपयोग की जाती है।
- पेट के अल्सर में मुलहटी का सेवन ठंडक देने के साथ ही लाभप्रद होता है। आंत की टीबी होने की स्थिति में भी मुलहठी फायदेमंद उपाय है।
- त्वचा या शरीर में कहीं जल जाने पर भी मुलहठी के चूर्ण और मक्खन का लेप एक कारगर उपाय है, साथ ही यह आंखों की रौशनी में भी वृद्धि करती है।

पेट से जुड़ी समस्याओं से हैं परेशान तो इन आसान उपायों से पाएं छुटकारा

लाइफस्टाइल में बदलाव का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। गलत खान-पान आपकी सेहत को प्रभावित करता है, ऐसे में पेट से जुड़ी समस्या का होना आम बात है। जैसे पेट दर्द, गैस, पेट का फुलना आदि। वहीं कुछ लोग पेट अच्छी तरह साफ न होने की शिकायत रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप पेट साफ न होने की समस्या से निजात पा सकते हैं।

- बदहजमी से परेशान है, तो आपको पुदीने का सेवन करना चाहिए। पुदीना पेट को साफ करने में मदद करता है। इसका सेवन आप चटनी के रूप में भी कर सकते है।
- सौंफ और सफेद जीरा पाउडर को पहले तवे पर भून लें और फिर उसे मिलाकर पीस लें। अब इस पाउडर का सेवन या तो दिन में एक बार करें या फिर अगर पेट साफ न होने की समस्या से ज्यादा परेशान हैं, तो इसका सेवन दो से तीन बार करें। आपको पेट साफ न होने की समस्या से राहत मिलेगी।
- नियमित रूप से सुबह के समय गुनगुना पानी पीने की आदत बनाएं। इसके कई फायदे हैं। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। साथ ही पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है।
- अजवाइन का बीज गैस और बदहजमी की समस्या को दूर करता है और तुरंत पेट को साफ करता है। इसके लिए आप अजवाइन के बीज को भूनकर रख लें और खाना खाने के बाद कुछ बीजों को रोज चबाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मिले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू

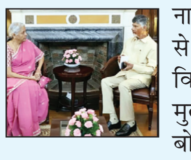

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पहले शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने कर्ज के बोझ दबे राज्य की वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि नॉर्थ ब्लॉक में बैठक के दौरान नायडू ने राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनके लिए उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। सूत्रों ने कहा, मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और बढ़े हुए आवंटन की मांग के पीछे के तर्क को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान तेलुगू देशम पार्टी के मंत्री मौजूद थे। राज्य सरकार के डेटा के अनुसार, राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश का ऋण 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 31.02 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 33.32 प्रतिशत हो गया है। यह पिछले पांच वर्षों में राज्य की राजकोषीय स्थिति में गिरावट का संकेत देता है।

दिल्ली हाई कोर्ट में बोले केजरीवाल, मैं आतंकवादी नहीं

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका के संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए निर्धारित की। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि आप नेता न तो भागने का जोखिम रखते हैं और न ही आतंकवादी हैं और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर, सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील डीपी सिंह ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किए बिना केजरीवाल के सीधे उच्च न्यायालय जाने पर आपत्ति जताई।

किताबों की छपाई में देरी, केंद्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना

नईदिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों की छपाई में देरी के बाद शिक्षा मंत्रालय पर बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्कूल वर्ष शुरू होने के बावजूद, एनसीईआरटी (नागपुर पढ़ें) शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 6 के छात्रों के लिए विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने में विफल रही है। रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण शिक्षण सामग्री समिति द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और उन्हें प्रिंट करने के लिए 10 से 15 दिनों की आवश्यकता होगी। कांग्रेस महासचिव ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों को छात्रों को किताबें उपलब्ध होने में दो महीने की देरी होने की उम्मीद है। नई पाठ्यपुस्तकें अप्रैल में पढ़ाई जानी थीं और अभी तक बाजार में नहीं आई हैं।

जम्मू-कश्मीर चुनाव में जनता सेवा का अवसर देगी : भाजपा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। भाजपा ने भी पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक के अलावा मंडल स्तर तक की बैठकें कर संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है। भाजपा को विश्वास है कि इस बार केंद्र शासित प्रदेश की जनता उसे सेवा का अवसर देगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर से मीडिया ने जब श्रीनगर में बात की तो उन्होंने कहा कि हम चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है इसलिए यहां के मतदाता हमारी पार्टी को उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत कश्मीर में डीडीसी, बीडीसी, नगर निगम और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए यह दर्शाता है कि यहां बड़ा बदलाव आ चुका है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को वंशवादी राजनीति ने बर्बाद कर दिया था।

विस चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

चंडीगढ़। एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में, हरियाणा सरकार ने 4 जुलाई को 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि 1990-बैच के अधिकारी अनुराग रस्तोगी को नया गृह सचिव नियुक्त किया। एक सरकारी आदेश के अनुसार, रस्तोगी को स्थानांतरित कर गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनके पास वित्त और योजना विभाग भी बने रहेंगे। रस्तोगी ने मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद से गृह सचिव का पदभार संभाला। शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल लोकसभा चुनावों के बाद कुछ समय से चल रहा था और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हुआ। एक सप्ताह से अधिक समय पहले, एक और बड़े फेरबदल में, हरियाणा सरकार ने 23 आईपीएस और 27 हरियाणा पुलिस सेवा अधिकारियों का तबादला कर दिया था।

भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार एक सहायक वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इससे सुरक्षा तंत्र को तो मजबूती मिलेगी ही, यह देश को आत्मनिर्भर भी बनाएगा।

प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से 'एक्स' पर पोस्ट की उस जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। सिंह ने कहा, "2023-24 में उत्पादन का मूल्य 1,26,887 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य की तुलना में 16.8 प्रतिशत अधिक है।"

प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा, "बहुत उत्साहजनक घटनाक्रम। उन सभी को बधाई जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने तथा भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के मकसद से एक सहायक वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे सुरक्षा तंत्र को बढ़ाएगा और हमें आत्मनिर्भर बनाएगा!"

इससे पहले, रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम साल दर साल नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है।

रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, रक्षा सामग्री बनाने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए सिंह ने कहा, "सरकार भारत को अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए और अधिक अनुकूल व्यवस्था सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

पूर्व वायुसेना प्रमुख का राहुल गांधी पर वार, बोले-

सेना को राजनीति में न घसीटें देश से मांगें माफी राहुल

नईदिल्ली। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता आरकेएस भदौरिया ने मृतक अग्निवीर के परिवार को मुआवजा न दिए जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया है। भदौरिया ने इस बात पर जोर दिया कि सेना और जवानों के परिवारों को राजनीतिक बहस से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना पहले ही इस मामले को संबोधित कर चुकी है और अग्निवीर अजय सिंह के रिश्तेदारों को दी गई अनुग्रह राशि के बारे में विवरण दे चुकी है।

आरकेएस भदौरिया ने कहा कि मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर को पेंशन को छोड़कर, एक सामान्य सैनिक की तरह समान व्यवहार और मुआवजा मिलता है। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बताया, भारतीय सेना पर भरोसा रखें, राजनीति का अनुसरण न करें और सेना में शामिल होने से पहले नियम और कानून खुद पढ़ें। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद अजय सिंह के परिवार को 98 लाख रुपये दिये जा चुके हैं और उन्हें 67 लाख रुपये और दिये जायेंगे। इस तरह अजय सिंह के परिवार को 1.65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इससे पहले, भारतीय सेना ने कहा है कि वह कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है और उनके परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभों का भुगतान शीघ्र ही पुलिस सत्यापन के बाद अंतिम खाता निपटान पर किया जाएगा। भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने बुधवार को अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले वेतन पर स्पष्टीकरण पोस्ट किया और कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि अग्निवीर के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

एडीजीपीआई ने कहा, इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को कुल देय राशि में से 98.39 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अग्निवीर शहीदों को मुआवजे को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सरकार को अल्पकालिक सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, ताकि देश को जमीनी स्थिति की वास्तविकता का पता चल सके।

हेमंत सोरेन के फिर मुख्यमंत्री बनने पर बोले प्रभारी शिवराज सिंह चौहान

ये घोर परिवारवाद है और सत्ता की भूख है

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री बदलने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) पर निशाना साधा। चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चौहान ने झामुमो पर तीखा हमला बोला। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने पिता और जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की मौजूदगी में राजभवन में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद इस साल फरवरी में चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

चौहान ने कहा कि यह घोर भाई-भतीजावाद और सत्ता की भूख है जो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर चंपई सोरेन की क्या गलती थी? उन्हें विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना चाहिए था। यह इस भावना को दर्शाता है कि केवल मैं ही रहूँगा और मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं रहेगा। हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए चौहान ने कहा कि बीजेपी न तो किसी को परेशान करती है और न ही बचाती है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। दिग्गज बीजेपी नेता ने कहा, बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और यहां चुनाव जीतकर फिर से सुशासन स्थापित करेगी।

शपथ लेने के तुरंत बाद, सोरेन ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए उन्हें सत्ता के नशे में धुत्त अहंकारी लोग कहा, जिन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आज झारखंड की जनता का जनमत फिर जागेगा। जय झारखंड, जय हिंद। एक वीडियो संदेश में, हेमंत सोरेन ने यह भी दावा किया कि विपक्ष ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को भूमि घोटाले में लगभग 5 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। शपथ लेने के 5 महीने बाद ही चंपई सोरेन ने पद से इस्तीफा दे दिया।

पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की रवानगी से पहले पीएम मोदी ने उनसे शुक्रवार को खास मुलाकात की और उन्हें विजय मंत्र दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से ओलंपिक 2036 की मेजबानी की भारत की दावेदारी कामयाब रहने को लेकर पेरिस में व्यवस्थाओं का अनुभव साझा करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों से व्यक्तिगत और आनलाइन बातचीत में कहा कि उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा मजबूत करने में काम आएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करें। इससे भी बड़ा माहौल बनता है और हम प्रयास कर रहे हैं। बुनियादी ढांचा तैयार करने पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, मैं ओलंपिक से पहले नहीं लेकिन बाद में वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने का आपसे आग्रह करूंगा । आप लोग भी खेल के बाद वहां व्यवस्थायें क्या हैं , उसे देखें । खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलेगा , वह 2036 के लिये काम आयेगा। आप यह देखकर आयेंगे तो हमें बहुत सुविधा होगी।

पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा है जिसमें भालाफेंक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण समेत सात पदक जीते।

खेल
प्रमुख समाचार

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का पहला टी20 मुकाबला आज

हरारे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में उतरेगी तो इस प्रारूप में यह भारतीय क्रिकेट के नये दौर का सूत्रपात भी होगा। भारत में टी20 विश्व कप की जीत के सतत जारी जश्न के बीच शुभमन गिल की कप्तानी वाली आईपीएल सितारों से सजी यह युवा टीम जीत का अपना सिलसिला शुरू करना चाहेगी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिये शानदार प्रदर्शन करने वाले पंजाब के अभिषेक शर्मा और राजस्थान रॉयल्स के लिये खेलने वाले असम के रियान पराग इस श्रृंखला के जरिये पदार्पण करेंगे। मैच का शाम 4.30 से शुरू होगा।

पिछले कुछ साल में रोहित और कोहली टी20 क्रिकेट में कई द्विपक्षीय श्रृंखलाओं से बाहर रहे हैं। अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दोनों के संन्यास के बाद उनकी कमी जरूर खलेगी। इसकी भरपाई करना तो मुश्किल है लेकिन फिर परिवर्तन संसार का नियम है। जिम्बाब्वे मजबूत टीम नहीं है लेकिन टी20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच बहुत गहरा अंतर नहीं है। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिये खेलने वाले सिकंदर रजा भारत के लिये चुनौती साबित हो सकते हैं। शिवम दुबे, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल तीसरे मैच से ही उपलब्ध होंगे।

भारत (पहले दो मैचों के लिये) - शुभमन गिल (कप्तान), रूतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, साइ सुदर्शन, जितेश शर्मा, हर्षित राणा।

जिम्बाब्वे- सिकंदर रजा (कप्तान), फराज अकरम, ब्रायन बेनेट, जोनाथन कैंपबेल, टेंडाइ चतारा, ल्यूक जोंगवे, इनोसेंट केइया , क्लाइव एम, वेसली मेदेवेरे, टी मारूमानी, वेलिंगटन मसाकाजा, ब्रेंडन मावुता, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डियोन मायर्स , एंटम नकवी, रिचर्ड एंगारावा, मिल्टन शुम्बा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स फिसलकर 80 हजार के नीचे आया

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में दो दिन से जारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया। एचडीएफसी बैंक, टाइटन, टाटा स्टील और एमएंडएम के शेयरों में बिकवाली के कारण शुक्रवार को बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 53.07 अंक यानी 0.07 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 79,996.60 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 79,478.96 और 80,149.87 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 21.70 अंक यानी 0.09 फीसदी की हल्की बढ़त देखी गई। निफ्टी दिन के अंत में 24,323.85 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,168.85 और 24,363.00 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 17 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। रिलायंस, एसबीआई, एनटीपीसी और एलएंडटी सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर रहे।

जून में शाकाहारी थाली की कीमत 10 प्रतिशत बढ़ी

नईदिल्ली। शाकाहारी थाली की कीमत जून में औसतन 10 प्रतिशत तक बढ़ गई। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में आई तेजी इसकी प्रमुख वजह रही। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की मासिक रिपोर्ट 'रोटी राइस रेट' के अनुसार, ब्रॉयलर मुर्गे की कीमत में गिरावट से मांसाहारी भोजन की लागत में कमी आई है। इसमें कहा गया कि शाकाहारी थाली की कीमत जून में 10 प्रतिशत बढ़कर 29.4 रुपये प्रति थाली हो गई, जो जून 2023 में 26.7 रुपये थी। मई 2024 में यह 27.8 रुपये थी। शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जियां (प्याज, टमाटर तथा आलू), चावल, दाल, दही और सलाद शामिल है। रिपोर्ट में शाकाहारी थाली की कीमत में कुल वृद्धि का कारण टमाटर की कीमतों में 30 प्रतिशत, आलू में 59 प्रतिशत और प्याज में 46 प्रतिशत की वृद्धि को बताया गया है।

कल्याण ज्वैलर्स का पहली तिमाही में राजस्व 27% बढ़ा

नईदिल्ली। कल्याण ज्वैलर्स का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में एकीकृत राजस्व सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़ा। भारतीय और पश्चिम एशिया बाजारों में मजबूत प्रदर्शन इसकी मुख्य वजह रही। कंपनी का वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में एकीकृत शुद्ध राजस्व 4,376 करोड़ रुपये था। कल्याण ज्वैलर्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत में उसके परिचालन में 29 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि देखी गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बिक्री में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पश्चिम एशिया परिचालन से राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने एकीकृत राजस्व में 15 प्रतिशत का योगदान दिया। कंपनी के अनुसार, इस साल अप्रैल-जून की अवधि में भारत में 13 नए फ्रेंचाइजी-स्वामित्व-कंपनी-संचालित (एफओसीओ) शोरूम खोले गए, जबकि डिजिटल मंच कैनडेयर ने 13 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की।

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में जून में 7 फीसदी गिरावट

नईदिल्ली। भारत में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में जून में सालाना आधार पर सात प्रतिशत की गिरावट आई। भीषण गर्मी के कारण शोरूम में आने वाले लोगों की संख्या में 15 प्रतिशत गिरावट इसकी बड़ी वजह रही। उद्योग निकाय फाडा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कुल यात्री वाहन पंजीकरण पिछले महीने 2,81,566 इकाई रहा, जबकि जून 2023 में यह 3,02,000 इकाई था। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, मांग को प्रोत्साहित करने के मकसद से बेहतर उत्पाद उपलब्धता तथा पर्याप्त छूट के बावजूद भीषण गर्मी के कारण ग्राहकों की संख्या में 15 प्रतिशत गिरावट आई और मानसून में देरी के कारण बाजार की धारणा सुस्त बनी हुई है। सिंघानिया ने कहा कि त्योहारी सीजन में अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए यात्री वाहन मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के लिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है।

पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले खतरों को डॉ हेडगेवार ने पहचान लिया था

प्रह्लाद सबनानी

आज पूरे विश्व में पूंजीवाद की तूती बोल रही है। लगभग समस्त देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवाद के सिद्धांत के आधार पर चला रहे हैं। मुक्त बाजार अथवा मुक्त उद्यम प्रणाली पूंजीवाद का दूसरा नाम है, जो उत्पादक संसाधनों पर निजी स्वामित्व के हक को मानते हुए देश में आर्थिक विकास को गति देने की नीति को अपनाती है।

पूंजीवादी सिद्धांत के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ का कहना था कि अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक धनकुबेर पैदा होने चाहिए, इससे अंततः वह देश विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो सकता है। अतः देश में धनकुबेर पैदा करने में शासन द्वारा आर्थिक नीतियों को उद्योगपतियों के हित में बनाया जाना चाहिए। इस सम्बंध में एडम स्मिथ ने वेल्थ आफ नेशन नामक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका होती है। इस अदृश्य शक्ति में शासन की नीतियों को भी शामिल किया जा सकता है। पूंजीवादी सिद्धांत पर आधारित आर्थिक नीतियों को अमेरिका में बहुत उत्साहपूर्वक लागू किया गया था। 1950 के दशक के बाद अमेरिका में इन सिद्धांतों के अनुपालन के पश्चात अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास दर बहुत तेजी से आगे बढ़ी और शीघ्र ही अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था। हालांकि, इस आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप देश में आर्थिक असमानता भी उतनी ही तेज गति से बढ़ती है क्योंकि देश में आर्थिक नीतियों को एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने की दृष्टि से विकसित किया जाता है, इससे अमीर और अधिक अमीर होते चले जाते हैं एवं गरीब और अधिक गरीब होते चले जाते हैं ।

विश्व में साम्राज्यवाद का सिद्धांत सबसे पुराना माना जाता है। शक्ति एवं प्रभुत्व बढ़ाने की राज्य की नीति मानी जाती रही है और इसकी समय समय पर वकालत भी की जाती रही है। कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण करके एवं कुछ क्षेत्रों पर राजनैतिक एवं आर्थिक नियंत्रण करके कुछ राज्य अपने वर्चस्व को बढ़ाते रहे हैं। ब्रिटिश शासन ने भी इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए दुनिया के कई देशों पर अपना राज्य कायम कर लिया था। इस सिद्धांत के अनुपालन से भी जिन राज्यों पर सत्ता स्थापित की जाती है उन राज्यों के नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना लिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। इस शासन प्रणाली में भी गरीब और अधिक गरीब हो जाते हैं और राज्य करने वाले देश के नागरिक शोषित राज्यों के संसाधनों का अति शोषण करते हुए इन्हें अपने हित में उपयोग करते हैं और वे स्वयं अमीर से और अधिक अमीर बनते चले जाते हैं।

पूंजीवाद के सिद्धांतों का अनुपालन करने वाले कुछ देशों, विशेष रूप से अमेरिका के विकसित देश हो जाने के पश्चात, ने भी बाद के समय में साम्राज्यवाद का चोला पहिन लिया था। इन पूंजीवादी देशों ने छोटे छोटे गरीब देशों के संसाधनों पर व्यापार के माध्यम से अपना हक जताना प्रारम्भ कर दिया था। शोषण करने वालों के केवल नाम बदल गए थे, क्योंकि राज्यों के स्थान पर अब पूंजीपति इन देशों के नागरिकों एवं संसाधनों का शोषण करने लगे थे। एक तरह से पूंजीवाद स्वयं ही राजा बन बैठा। वैसे भी पूंजीवाद के सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली अर्थव्यवस्था में येन केन प्रकारेण लाभ कमाना ही मुख्य लक्ष्य होता है, चाहे इसके लिए किसी वर्ग अथवा देश का शोषण ही क्यों न करना पड़े।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय प्रथम संघचालक डॉक्टर हेडगेवार ने वर्ष 1920 के पूर्व ही पूंजीवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों को पहचान लिया था तथा वे पूंजीवाद की आड़ में विश्व में फैल रहे साम्राज्यवादी नीतियों के भी घोर विरोधी थे। साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत कुछ पूंजीवादी देश, विश्व के अन्य गरीब देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। ब्रिटेन ने भी भारत पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के माध्यम से ही आधिपत्य स्थापित किया था।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में शासन और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ युवा गोठ का मॉक सदन

फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को समाप्त करने और पर्यावरण पर जागरूकता के साथ ही प्रकृति का संरक्षण संभव हैः विस अध्यक्ष

रायपुर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित ऑडिटोरियम में प्रदेश सरकार, यूनिसेफ और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से युवा गोठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 146 विकासखंडों से आए 150 युवा प्रतिनिधियों, जिसमें विशेष रूप से बस्तर संभाग के युवाओं ने भागीदारी की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन का प्रारूप बनाकर चर्चा की। इस चर्चा के उपरांत श्रीकांत पांडे, स्टेट डायरेक्टर, नेहरू युवा केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डॉ रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए डेढ़ दशक के

कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। भाजपा की डेढ़ दशक की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने युवाओं पर विशेष ध्यान दिया और कौशल उन्नयन के लिए कानून बनाकर संवैधानिक अधिकार दिया था। इसके साथ ही प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में राज्य निर्माण के बाद से ही वृक्षारोपण की पहल और वनांचलों के बेहतर रखरखाव के लिए भी भाजपा सरकार ने अपना दायित्व निभाया था। इस संबोधन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सक्रीय 16 युवा मितानों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने युवा गोठ का वीडियो लांच किया।

इसके उपरांत छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने अपना संबोधन किया जिसमें उन्होंने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रकृति के संरक्षण और जलवायु के महत्व पर युवाओं को संबोधित किया और युवा गोठ के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे देश में संचालित हो रहा है और हर नागरिक इस अभियान से जुड़कर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहा है। प्रदेश और देश में बढ़ते तापमान और छत्तीसगढ़ के पर्यावरण संवर्धन की दिशा में जन-जागरूकता प्रसारित कर रहे यूनिसेफ, नेहरू युवा केंद्र के युवा साथियों के योगदान के लिए उन्होंने आभार प्रकट करते हुए ऐसे आयोजनों को समाज और पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम में आगे मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने अपना प्रेरक संबोधन दिया उन्होंने कहा कि आज प्रदेश

के युवा संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप पर्यावरण परिवर्तन और जलवायु संरक्षण जैसी राष्ट्रव्यापी समस्या पर इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, यह न केवल युवा विचारधारा को दिखाता है बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य कितना सजग, जागरूक और प्रकृति को लेकर संवेदनशील है।

उन्होंने कहा कि जब प्रकृति में मौजूद पंच महाभूत का संतुलन बिगड़ जाता है, तब प्रकृति का विकराल स्वरूप दिखाई देता है। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर एक चिंताजनक स्थिति बन गई है तब इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड के दौर में हिंदुस्तान के साथ-साथ पूरी दुनिया को यह मालूम हुआ कि ऑक्सीजन जोकि प्रकृति हमें बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाती है, उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने आगे कहा कि हमारे शरीर का 50-70त्न हिस्सा पानी का हिस्सा होता है, पृथ्वी पर चारों दिशा में पानी दिखाई पड़ता है लेकिन इसमें 97त्न पानी समुद्र का खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है, शेष बचे 3त्न पानी में 2.5त्न पानी ग्लेशियर में जमा हुआ है जिससे पिघलकर नदियाँ बनती हैं।

गीली मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे, जैसा आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं

रायपुर। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और यह बिल्कुल ही गीली मिट्टी की तरह होते हैं.. आप इन्हें जिस रूप में आकार देना चाहते हैं, दे सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कुम्हार की चाक पर हाथ चलाते हुए राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शायद यहीं संदेश दे रहे थे। जशपुर जिले में अपने गृहग्राम बगिया में मुख्यमंत्री श्री साय ने अपनी पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय के साथ कार्यक्रम स्थल पर चाक पर न सिर्फ हाथ आजमाए...उन्होंने गीली मिट्टी से दीया बनाकर मौके पर उपस्थित बच्चों और अभिभावकों को अलग-अलग संदेश दिया कि गीली मिट्टी की तरह बच्चे भी कोमल होते हैं और उन्हें किसी भी रुप में ढाला जा सकता है। वहीं दीया बनाकर उन्होंने अँधेरे को दूर करने में दीये की उपयोगिता को बताने की भी कोशिश की।

इस दौरान बगिया में कार्यक्रम स्थल पर लगायें एक-एक स्टाल का मुख्यमंत्री श्री साय ने अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार मॉडल,सामग्रियों को देखकर उनकी सराहना की और उन्हें प्रेरित भी किया।

राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग विभागों की स्टाल लगाई गई थी। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने मॉडल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया के रोकथाम, आदिवासी विकास विभाग द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालय में अध्यापन और आदिवासी बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं, लाइवलीहुड कॉलेज नवगुरूकुल द्वारा आजीविका पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई। स्टाल में पीएमश्री प्राथमिक शाला लवाकेरा के विद्यार्थियों ने बैंड से देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की। शासकीय कन्या आश्रम बगीचा, पीएमश्री विद्यालय कांसाबेल, पीएमश्री विद्यालय कडरेगा के बच्चों ने स्कूल में तैयार की गई मॉडल, वैज्ञानिक सोच और तार्किकता को बढ़ावा देने वाले मॉडल से मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचा। छात्रा कु.अनामिका ,समिस्ता टोप्पो, दीपिका सिंह,दृष्टि साय, अनुष्का टोप्पो ने जादुई पिटारे सहित अन्य प्रस्तुत सामग्रियों के विषय में बताया। शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला पत्थलगांव के विद्यार्थियों ने हुनर के पेटी,खेल सामग्री ,जादुई पिटारा,बायो गैस मॉडल के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

लक्ष्य निर्धारित कर अपनी सीमा न बांधे विद्यार्थी : साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर के धनेली स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में श्री सदगुरू प्राकट्य महोत्सव और स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और इंडो-नेपाल यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं और प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ और भारत में पिछले सात वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के साथ ही संस्कार और अध्यात्म से भी जुड़ा है। यहां विदेशों से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से ही भारत पूरी दुनिया को देते आया है। चिकित्सा, विज्ञान, वेद, आध्यात्म जैसी चीजें भारत ने दुनिया को दी हैं।

हमारी संस्कृति और कल्पना इतनी व्यापक है कि श्वसुधैव कुटुंबकमश् को अपनाते हुए हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बीते दस वर्षों में विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मजबूत भारत के निर्माण की नींव इन दस वर्षों में रखी गई है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर अपने लिए सीमा मत बाँधिए। आप अपने विषय और अपने क्षेत्र में समर्पण और निष्ठा से काम करें। एक दिन आप शिखर पर होंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया कि आप अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत और लगन से आप भी शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।

जनसहयोग से खैरागढ़ में खुला प्रदेश का दूसरा एस्ट्रोनॉमी लैब

रायपुर। जिले के स्कूली छात्र-छात्राओं को आज बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश का दूसरा और संभाग का पहला एस्ट्रोनॉमी लैब खैरागढ़ शहर स्थित शाला क्रमांक 2 में बनाया गया है, जिसका शुभारंभ राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने किया. बता दें कि खैरागढ़ शहर की इस शाला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पढ़ाई की थी. इस स्कूल का भवन

बीते कुछ वर्षों से जर्जर हो चुका था, जिसको जनभागीदारी जनसहयोग से एस्ट्रोनॉमी लैब में परिवर्तित किया गया है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी नीलिमा राजपूत ने बताया कि लगभग डेढ़ साल की मेहनत के बाद यह एस्ट्रोनॉमी लैब बनकर तैयार हुआ है. इसे बनाने के लिए यहां के पूर्व छात्र, नगर के समाजसेवी और शिक्षकों की एक टीम बनाई गई और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लेकर चर्चा की गई. इसके बाद जन सहयोग से यह लैब बनकर तैयार हुआ है. सांसद संतोष पांडे ने जनसहयोग से तैयार इस लैब को सराहा. उन्होंने कहा कि शहर के समाजसेवियों के सहयोग से यह संभव हुआ है, जिससे बच्चों को एस्ट्रॉनामी समझने में आसानी होगी.

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

भाजपा के विधायक और नेता कानून का मखौल उड़ा रहे हैं

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है जंगल राज कायम हो गया है। भाजपा के विधायक और नेता कानून का मखौल उड़ा रहे हैं विधायक ईश्वर साहू के पीए पुलिस जवान के साथ मारपीट करते हैं, भिलाई के विधायक रिकेश सेन पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दिए गए सरकारी बंगले पर जबरदस्ती अपने लोगों के साथ प्रवेश करते हैं। जनकपुर जनपद पंचायत भरतपुर के जनपद उपाध्यक्ष भाजपा नेता दुर्गा शंकर मिश्रा ने तहसीलदार के साथ गाली गलौज किया उन्हें देख लेने की धमकी दिया। आरंग में अवैध खनन रोकने गए अधिकारी के साथ मारपीट किया गया। कहीं पटवारी को धमका रहे हैं तो कहीं अन्य विभाग के अधिकारियों को धमका रहे। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? प्रदेश में नियम कायदे हैं भी कि उन्हें भी फ्रीज कर दिया गया। जब भाजपा के नेता और विधायक ही कानून को ठेंगा दिखाएंगे ऐसे में आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। यह घटनाएं पुलिस के आत्म बल को तोड़ने वाली है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी पर भाजपा नेताओं का खौफ दिख रहा है कुछ दिन पहले भाजपा के कार्यकर्ता ने एसडीएम को धमकाने का भी काम किया था स्कूलों के शिक्षकों को डराया धमकाया जा रहा है।

18 लाख आवास का दावा करने वाली साय सरकार ने एक भी आवास नहीं बनाया - कांग्रेस

रायपुर। उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा केन्द्रीय आवास मंत्री मनोहर खट्टर से छत्तीसगढ़ के लिये 18 लाख आवासो की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही 18 लाख लोगो को आवास दिया जायेगा। मुख्यमंत्री सीएम हाउस में बाद में प्रवेश करेंगे, पहले आवास आवंटित होगा। हकीकत यह है कि राज्य में भाजपा की सरकार बने 6 माह हो गया, अभी तक साय सरकार ने एक भी आवासहीन के लिये आवास नहीं बनाया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिनके लिये आवास स्वीकृत किया था उनको भी दूसरी किश्त भाजपा सरकार नहीं दे पाई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधानमंत्री आवास के मकानों की संख्या को स्वीकृति ही नही दिया है। राज्य सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवास हीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये।

कोल माफिया राज वर्चस्व स्थापित करने भाजपाई गोलीबारी कर रहे

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकारी ठेकों कोयला और जमीनों के कारोबार पर कब्जा के लिये भाजपाईयों में गैंगवार छिड़ा हुआ है। रायगढ़ जिले से लगे सुन्दरगढ़ बार्डर पर भाजपा के दो गुट के नेताओं के बीच कोयला कारोबार के वर्चस्व को लेकर सरे आम गोलीबारी की घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शी बताते है इस मामले में घंटो तक गोलियां और धारदार हथियार चलाये गये। दो ढाई सौ लोग हथियार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े थे। इस पूरे मामले में भाजपा के एक पूर्व विधायक का पुत्र तथा वर्तमान सरकार के मंत्री के खास लोगो की संलिप्तता है। उड़ीसा में इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस पूरे गैंगवार के पीछे छत्तीसगढ़ की पुलिस क्यों खामोश है? सारे लोग रायगढ़ से जुड़े है, फिर इतने बड़े घटना पर छत्तीसगढ़ का पुलिस कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? इतनी बड़ी घटना पर छत्तीसगढ़ पुलिस का कोई कार्यवाही नहीं करना इस बात का प्रमाण है। कोयले के इस काले कारोबार का पूरी सरकार को संरक्षण है तथा कोयले की काली कमाई ऊपर तक पहुंच रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है।

महिलाओं को कानूनी मदद देगा हेल्प लाइन नंबर-181

रायपुर। संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 181 है जो 24 घंटे सातों दिन कार्यरत है। जिस पर कोई भी महिला, जो किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, या यौन प्रताड़ना का शिकार है, कॉल कर सकती है। महिला हेल्पलाइन पीड़ित महिला की शिकायत को सुनकर प्रकरण के तर्कसंगत समाधान हेतु प्रयास करती है। इस हेतु वह राज्य के सभी जिलो के सखी वन स्टाप सेंटर, संबंधित थाना एवं आपातकालीन स्थिति में 112 से समन्वय स्थापित करती है। महिला हेल्पलाइन किसी भी संकटग्रस्त महिला की सहायता हेतु टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर कॉल कर महिला 24 घंटे सातों दिन मदद ले सकती है। कोई भी महिला जो किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना से ग्रस्त है, वह इस नंबर पर कॉल कर सकती है। इन मामलों में घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, छेड़छाड़ टोनही प्रताड़ना कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, साइबर काईम दहेज प्रताड़ना एवं अन्य सभी अपराध शामिल है, जिसमें महिला शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताडित हो। सर्वप्रथम पीड़िता का कॉल आने पर उनकी समस्या को सुनकर समस्या को समझा जाता है। पीड़िता की

जंगल सफारी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण

रायपुर। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी सुधीर अग्रवाल ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत पौधा रोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गयी थी द्य जंगल सफारी नया रायपुर में आज से पौधारोपण कार्यक्रम की सुरुवातकी गई है जिसमें कुल 6000 पौधे लगाये जा रहे है । कार्यक्रम में एपीसीसीएफ प्रेमकुमार, सीसीएफ वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक उदंती सीतानदी विश्वेश झा, संचालक जंगल सफारी गणवीर धम्मशील ने भी पौधरोपण किया। जंगल सफारी के संचालक धम्मशील ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जंगल सफारी में पर्यटक और नागरिक 20 जुलाई तक पौधा रोपण कर प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते है । इस अवसर पर जंगल सफारी के सहायक संचालक और अन्य स्टॉफ भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने की जल जीवन मिशन अंतर्गत एजेंसियो के कार्यो की समीक्षा

भुगतान रोकने के बाद भी प्रगति नही लाने वाले एजेंसी होंगी ब्लैकलिस्टेड

रायपुर। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में जल जीवन मिशन कार्य के लिए अनुबंधित एजेंसियो की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होने सभी एजेंसियो के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कम प्रगति वाले एजेंसी का भुगतान रोका जाएगा, इसके बाद भी सुधार नही लाने पर एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कमजोर फिल्ड वर्क के कारण हेल्प एंड हेल्प एजेंसी के कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं ।

कलेक्टर ने बैठक के दौरान एजेंसियों के कार्य की जमीनी हकीकत जानने फिल्ड पर काम कर रहे कर्मचारियों से सीधे फोन पर बात कर जानकारी ली और जरुरी निर्देश दिए। उन्होने सभी एजेंसियो से प्रतिदिन किये गए कार्य की रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने ऐसे एजेंसी जिनके पास आवंटित गांव की संख्या अधिक और कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है उनसे गाँव की संख्या कम कर बेहतर प्रगति वाले एजेंसी को देने कहा।

कलेक्टर ने कहा कि सभी एजेंसी गुणवत्तापूर्ण काम करें, अब तक

जो काम अधूरे है उसे जल्द पूरा करें तथा पाईप बिछाने खोदे गए गड्ढों को ठीक करें। उन्होने कहा कि सभी जल स्त्रोतों का टेस्टिंग किट से जल की गुणवत्ता जाँच एवं क्लोरीनिकरण करें। जल जीवन मिशन में सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण कार्य हो उसके बाद ग्रामवासियों को यूजर चार्ज के लिए प्रोत्साहित करें। बरसात के मौसम में जलजनित बीमारियों से बचने सभी गांव में बैठक लेकर लोगों को समझाइश दें कि पानी उबालकर ठंडा होने के बाद पीने के लिए उपयोग में लाएं। बताया गया कि विकासखंड बलौदाबाजार में एजेंसी उपवन महिला बाल विकास को 146 गाँव, पलारी में एजेंसी हेल्प एंड हेल्प को 132 गाँव, भाटापारा में एजेंसी कामगार फाउंडेशन को 108 गाँव, कसडोल में एजेंसी विकास आशा सेवा समिति को 117 एवं एजेंसी प्रतीक्षा को 110 गांव कार्य करने हेतु आवंटित किया गया है।

छत्तीसगढ़ की यात्री सुविधा बदहालः बघेल

रायपुर। पत्रकारों से चर्चा करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यात्री सुविधा बदहाल है। 1000 से अधिक ट्रेने रद्द हो गयी है और वह माल लदान का काम है वह रिकार्ड बना रहा है छत्तीसगढ़ में। यात्रियो के साथ लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे की व्यवहार कर रही है जो घोर निंदनीय है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को ध्यान देना चाहिये। केन्द्र सरकार में 10-10 सांसद जीत कर आये है उनको इस मामले में पहल करनी चाहिये और यहां के यात्रियों को जो सुविधा मिल रही थी वह जारी रहे। रेडी टू ईट का पेमेंट नहीं हुआ और शालाएं शुरू हो गयी है और बच्चों को रेडी टू ईट मिल नहीं रहा है और यह कहा जा रहा है कि बीज निगम से पेमेंट नहीं हुआ। पिछले सत्र में उसको निरस्त करने की घोषणा विधानसभा की थी और सेल्फ हेल्थ ग्रुप को देने की बात कही थी लेकिन घोषणा बस कर दिये लेकिन कार्यवाही करना भूल गये। यदि सेल्फ हेल्थ ग्रुप को दिया जाता तो अभी तक के उत्पादन शुरु कर देते लेकिन किये नहीं। बहुत जोर शोर से विधानसभा में घोषणा किये थे लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं। इस प्रकार से बच्चों के साथ जो नेशनल प्रोग्राम है और बच्चों से न्यूटिर जो मिलना था

उसको भी वंचित कर दिये। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव ऐप में एफआईआर कहां हुआ है केवल छत्तीसगढ़ में हुई हैं। सभी आरोपी को पकड़-पकड़कर कोई हैदराबाद से मुंबई, गोवा, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली से ला रहे है और देश भर के अनेक राज्यो से पुलिस पकड़-पकड़कर ला रहे है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.